





## सिक्किम में सेना का ऑपरेशन हिमराहत जारी

### ● बर्फबारी में फंसे 46 टूरिस्टों को सफलता से बचाया

गंगटोक (एजेंसी)। भारतीय सेना ने अचानक हुई बर्फबारी के कारण सिक्किम के शेरथांग बेल्ट के आसपास फंसे 46 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया है। सेना के मुताबिक, ऑपरेशन हिमराहत के तहत रेस्क्यू किए पर्यटकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। टूरिस्ट को मौसम के हालात ठीक होने और सड़कें साफ होने तक 17 एमएम माइल पर आर्मी ट्रांजिट केप में शिफ्ट कर दिया गया। बर्फबारी में करीब 350 गाड़ियों फंस गई थीं। टूरिस्ट को 150 गाड़ियों से रेस्क्यू किया गया। अभी तक 46 पर्यटकों को ट्रांजिट



कैप में रखा गया है। बचाव-राहत का काम अभी भी जारी है। एएनआई के मुताबिक रविवार सुबह चांगू नाथला में बर्फबारी के बाद शेरथांग बेल्ट के जेएन रोड पर सिप्सू और 16एमएम माइल के बीच त्सांगू के पास करीब 350 टूरिस्ट गाड़ियां फंस गईं। ये सभी टूरिस्ट त्सांगू जा रहे थे, जो सिक्किम का पॉपुलर डेस्टिनेशन है। भारतीय सेना सावधानी बरतते हुए इस इलाके में वाहनों की आवाजाही रोक दी। इसके बाद ऑपरेशन हिमराहत शुरू किया। रास्ते में फंसे पर्यटकों और ड्राइवर्स को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस, आर्मी और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया।

## कोटद्वार के 'मोहम्मद दीपक' से मिले राहुल गांधी

### ● नफरत के माहौल में मोहम्मद की दुकान का प्रतीक बताया

कोटद्वार (एजेंसी)। कोटद्वार के पटेल मार्ग में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के बाद चर्चाओं में आए 'मोहम्मद' दीपक कुमार से सोमवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भेंट की। इस दौरान राहुल गांधी ने पुनः दीपक कुमार को इंसाइनयत की मिसाल बताया। बताते चलें कि बीती 26 जनवरी को पटेल मार्ग स्थित एक दुकान का नाम बदलने को



लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान कोटद्वार में जिम संचालक दीपक कुमार ने स्वयं को मोहम्मद दीपक बताते हुए दूसरे पक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। स्वयं को मोहम्मद दीपक बताने वाला वीडियो 28 जनवरी से सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गया। घटना के चार दिन बाद 31 जनवरी को देहरादून सहित अन्य स्थानों से पहुंचे हिंदू संगठनों ने 26 जनवरी के दिन हिंदू संगठनों पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर कोटद्वार में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद दुकान स्वामी पटेल मार्ग निवासी वकील अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले 30 साल से 'बाबा स्कूल ड्रेस' नाम से दुकान चला रहे हैं।

## कनाडा के 3 पंजाबी सांसदों की सीक्रेट विजिट पर विवाद

### ● पूछा जा रहा-यात्रा पर खर्च किसने किया

लुधियाना (एजेंसी)। कनाडा में मुख्य विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के पंजाबी मूल के 3 सांसदों की पंजाब यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं।

कनाडा में सोशल मीडिया पर तीनों कंजर्वेटिव सांसदों से पूछा जा रहा है कि उनकी इस यात्रा का खर्च किसने उठाया।

कनाडा के सांसद जसरज सिंह हल्लां, अमरप्रीत सिंह गिल और दलविंदर सिंह गिल पंजाब यात्रा पर आए थे। यात्रा का कारण और इस यात्रा के बारे में जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यही नहीं, सांसदों के आसपास हथियारबंद निहों के होने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यात्रा से जुड़ी बातें और



अन्य गतिविधियों से जुड़े फोटो-वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। इसके बाद सांसदों की यात्रा का खुलासा हुआ।

● गोल्डन टैपल, गुरु की रसोई व परगट सिंह से मिले- तीनों सांसद 15 फरवरी को अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब (गोल्डन टैपल) गए और वहां माथा टेका। उसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उन्हें सम्मानित किया। सदस्यों व अन्य धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद वह कांग्रेस

विधायक परगट सिंह से मिले और उनके साथ इमीग्रेशन के मुद्दे पर बातचीत की। बाद में वे होशियारपुर में गुरु की रसोई में गए।

## योगी ने सिंगापुर में किए 6 हजार करोड़ के समझौते यूपी में 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

लखनऊ (एजेंसी)। सीएम योगी सिंगापुर दौरे पर हैं। उन्होंने कारोबारियों के साथ बैठक की। यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। यूनिवर्सल सर्वसेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह निवेश यूपी में 'एडवेंसिंग', लॉजिस्टिक्स और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे अहम क्षेत्रों में किया जाएगा। इनसे 20 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने निवेशकों को मुद्दे पर बातचीत की। बाद में वे मजरी दे रहे हैं। यूपी की 25 करोड़ से ज्यादा

की बड़ी आबादी एक बड़ा बाजार है। कानून-व्यवस्था बेहतर है, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी मजबूत हो रही, जिससे लंबे समय के निवेशकों को फायदा मिलेगा। सुरेश खन्ना और उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी नजर आए। नंदी और वित्त मंत्री कोट-पैट पहने हुए थे, जबकि सीएम पारंपरिक परिधान यानी भगवा कपड़ों में नजर आए। सीएम 3 दिन में 25 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 25 फरवरी को जापान पहुंचेंगे।



भगवा कपड़ों में नजर आए। सीएम 3 दिन में 25 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 25 फरवरी को जापान पहुंचेंगे।

## जम्मू-कश्मीर में सेना का 326 दिनों का ऑपरेशन सफल

### व्हाइट नाइट कोर ने किया सैफुल्ला समेत 7 खूंखार आतंकियों का सफाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपने सफल ऑपरेशन को लेकर विस्तृत जानकारी शेयर की है, जहां आतंकियों के नेटवर्क को सुरक्षाबलों ने एक बड़ा झटका दिया है। यह घटना सुरक्षा बलों द्वारा किश्तवार जिले में एक मुठभेड़ में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के तीन सदस्यों को मार गिराए जाने के एक दिन बाद हुई है, जिनमें सबसे वांछित आतंकवादी सैफुल्लाह भी शामिल था। दरअसल, एक्स पर एक पोस्ट में, सेना के व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि उसने किश्तवार क्षेत्र में 326 दिनों तक अथक और ऊंचाई वाले संयुक्त



अभियान चलाए। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने कड़क की टंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुर्गम इलाकों में आतंकवादियों का पीछा किया, जिसके परिणामस्वरूप कई मुठभेड़ें हुईं। व्हाइट नाइट कोर ने कहा

है कि इसमें नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा स्थापित एक सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क के आधार पर व्हाइट नाइट कोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सीआरपीएफ के जवानों ने अंततः जीत दर्ज की।

● खुफिया एजेंसियों के दृढ़ संकल्प, साहस और शौर्य से मिली सफलता- सेना ने कहा, अभियानों में सहायता के लिए एफपीवी ड्रोन, उपग्रह इमेजरी, आरपीए/यूपीवी, संचार आदि जैसी तकनीक का लगातार उपयोग किया गया। सैफुल्लाह और उसके साथियों के खाले में परिणत हुई हमारी सेनाओं की अथक खोज और दृढ़ संकल्प यह साबित करता है कि वदीधारी हमारे जवानों और खुफिया एजेंसियों के दृढ़ संकल्प, साहस और शौर्य के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि इसमें नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा स्थापित एक सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क के आधार पर व्हाइट नाइट कोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सीआरपीएफ के जवानों ने अंततः जीत दर्ज की।

● जंगलों और रिहायशी इलाके के आसपास भी रही नजर- सेना को किश्तवाड़ के जंगलों और रिहायशी इलाके के आसपास छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। इनमें सैफुल्लाह भी शामिल था, जो कि एक मोस्ट वांटेड आतंकी था। सेना ने इनकी घेराबंदी करने और इनमें भागने से रोकने के लिए सभी एंटी और एंजिजट पाइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया था। ऐसे में लंबे एनकाउंटर के बाद इन सभी आतंकियों को मार गिराया गया है। रमजान के महीने की शुरुआत से एक दिन पहले यानी 18 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के उपायुक्त पंजाब कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, सरकार, वफ बोर्ड या किश्तवाड़ की जामिया मस्जिद के इमाम की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन या धार्मिक एवं धर्मार्थ संगठन रमजान के महीने के दौरान चंदा इकट्ठा नहीं कर सकता।

### पश्चिम बंगाल की जनता के लिए...

## पीएम ने लिखी चिट्ठी

### सीएए का जिफ्र करतें हुए की बांग्लादेशी घुसपैट पर लगाम की बात

### राज्य के विकास के साथ कानून-व्यवस्था पर भी रखे अपने विचार



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सीएए का जिफ्र करतें हुए घुसपैट पर लगाम, राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी है।

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ने पत्र की शुरुआत जय मां काली के जयकारे के साथ की। उन्होंने लिखा कि अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जायेगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके स्रोच-समझे फैसले पर निर्भर करता है। मेरे सोचने बंगाल के सपने देखने वाला हर एक जवान, बूढ़ा और महिलाएं आज बहुत पीड़ा में हैं। उनकी पीड़ा से आज मेरा हृदय भी व्यथित है।

● वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाया - 'अटल पेंशन योजना' के तहत 56 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। 'उज्वला योजना' के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस देकर माताओं-बहनों को धुएँ से मुक्ति दिलाकर मैं धन्य हूँ। जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, आज पश्चिम बंगाल में वही अन्नदाता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति में 'किसान सम्मान निधि' के जरिए 52 लाख से अधिक किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई है।

## नेपाल में बस हाईवे से नदी में गिरी, 18 की मौत

### 25 घायल, मरने वालों में 2 विदेशी

### नागरिक, कंट्रोल खोने से हादसा

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल के धादिंग जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि, यह किस देश से थे और इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। आर्म्ड पुलिस फोर्स के मुताबिक, अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाद में एक अन्य यात्री की मौत की पुष्टि हुई, जिससे

मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया। हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू कर अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी किसी कारण ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस त्रिशूली नदी में जा गिरी।

## स्कूटर क्लब में छात्रों का चाकूओं से गोदा

### ● कोचिंग के दो साथियों ने तमाचे का बदला लिया; 30 सेकंड में 27 वार किए

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 10वीं कक्षा के एक छात्र पर दो नाबालिग छात्रों ने पूल गेम खेलते समय चाकू और छुरी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना 15 फरवरी की रात टीला जमालपुर स्थित गणेश चौक के एक स्कूटर क्लब में हुई।

आरोपियों ने 30 सेकंड में 27 बार चाकू और छुरी मारी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज 22 फरवरी को सामने आया है, जिसमें आरोपी फिल्मी अंदाज में अंदर घुसते और ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए।

घायल छात्र किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। हमले में उसकी एक कलाई पर 10 से अधिक गहरे कट लगे हैं, जबकि दूसरे हाथ की दो उंगलियां कट गई हैं। कंधे और पीठ पर भी गंभीर चोटों के निशान हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस के अनुसार, घायल 16 वर्षीय छात्र गौतम नगर थाना क्षेत्र का निवासी है और रोजाना पूल खेलने

क्लब आता था। कुछ दिन पहले उसका क्लब में ही 16-16 वर्षीय दो अन्य नाबालिगों से विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि उस दौरान छात्र ने दोनों को थपड़ मार दिए थे। इसी रंजिश में आरोपियों ने बदला लेने की नीयत से हमला किया।

हमला करने वाले दोनों नाबालिग भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और घायल के साथ कोचिंग में पढ़ते हैं। पूल गेम में वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों में पहले भी तनातनी हो चुकी थी। पुलिस कार्रवाई पर सवाल, आरोपियों को नोटिस देकर थाने से छोड़

पुलिस ने साधारण धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद नोटिस देकर थाने से छोड़ भी दिया गया। मामले में सब इंस्पेक्टर मनपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। दोनों ही नाबालिग बालकों को थाने से नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। मैडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आगे धाराओं में इजाफा होगा।

## एमपी के कूनो में चीतों की 'हाफ सेंचुरी' की तैयारी

### समंदर पार से उड़कर आ रही है 8 चीतों की नई खेप

श्यांपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश में चीतों को फिर से बसाने और उनकी सुरक्षा के प्रयासों को बड़ा बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 28 फरवरी तक बोत्सवाना से 8 और चीते मध्य प्रदेश आ जाएंगे। यह कदम इस साल के अंत तक राज्य में चीतों की संख्या 50 तक पहुंचाने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। इसी बीच, दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क में तीन शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में चीता पुनर्जनन परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इसने 'प्रकृति से प्रगति' का एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का



आभार व्यक्त किया और कहा कि 'प्रोजेक्ट चीता' दुनिया का सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण अभियान बनकर उभरा है। शनिवार को सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञापन जारी कर 'प्रोजेक्ट चीता' के 'तीन सफल वर्षों' पर प्रकाश डाला। विज्ञापन में कहा

गया, भारत की चीता विलुप्ति के बाद उन्हें फिर से देश में बसाने की पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विज्ञापन में आगे कहा गया, सितंबर 2022 में शुरू हुई यह संरक्षण यात्रा लगातार जारी है।

● चीतों को जम गई कूनो की आबोहवा- नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते भारतीय परिस्थितियों में अच्छी तरह से ढल गए हैं। कूनो और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में दूसरी पीढ़ी के शावकों का जन्म सीएम मोहन यादव के प्रभावी नेतृत्व में पीएम मोदी के दृष्टिकोण की प्रगति को दर्शाता है। भारतीय अभयारण्यों में चीतों को दौड़ते देखना जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। इससे पहले, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो नेशनल पार्क के संरक्षित बाड़ों में छोड़ा था, जिसने महत्वाकांक्षी चीता पुनर्जनन परियोजना की औपचारिक शुरुआत की थी। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में लाया गया था। सरकार का लक्ष्य 2032 तक लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 60-70 चीतों की एक आत्मनिर्भर आबादी स्थापित करना है।

● प्रोजेक्ट चीता पर सरकार की प्लानिंग- 28 फरवरी तक बोत्सवाना से 8 नए चीते एमपी की धरती पर कदम रखेंगे, जिससे कूनो की रौनक और बढ़ेगी। सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में 'मिशन 50' का ऐलान किया है, यानी इसी साल के भीतर चीतों की संख्या 50 पार कराने की तैयारी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने 18 फरवरी को 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे प्रोजेक्ट को बड़ी मजबूती मिली है। सीएम ने इस अभियान को 'प्रकृति से प्रगति' का संदेश बताया है और इसके लिए पीएम मोदी के विजन का आभार जताया है। सरकार केवल कूनो ही नहीं, बल्कि गांधी सागर और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में भी चीतों का घर बसाने की लंबी योजना पर काम कर रही है।

## रिश्तों में आई नई गर्माहट, व्यापार और तकनीक में भी बढ़ेंगे साथ

### ● भारत की मेजबानी देख भावुक हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला

### भारत-ब्राजील व्यापार लक्ष्य 30 अरब डॉलर तक बढ़ाया गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने भारत यात्रा के दौरान मिले सांस्कृतिक सम्मान और आत्मीय आतिथ्य की खुलकर सराहना की। इंडिया-ब्राजील इकोनामिक फोरम में उन्होंने कहा कि राजकीय भोज और दोपहर के भोजन के दौरान भारतीय संगीतकारों द्वारा ब्राजीलियाई गीतों की प्रस्तुति से वह अचंचित और भावुक हो गए। राष्ट्रपति लूला ने याद किया कि पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील गए थे, तब उन्होंने साओ पाउलो से गायक बुलाकर



प्रधानमंत्री के पसंदीदा गीत की प्रस्तुति पैलेसियो डा अल्बोराडा में कराई थी। उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा दिल रखता है।

● दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य- दोनों देशों के बीच व्यापार 2.4 अरब डॉलर से बढ़कर 10.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जहां 2030 तक 20 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा गया था, वहीं लूला ने इसे बढ़ाकर 30 अरब डॉलर तक ले जाने की महत्वाकांक्षा जताई। यात्रा के दौरान भारत के केंद्रीय औद्योगिक नियंत्रण संगठन और ब्राजील की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ।

## परिष्कार

## एआई स्टेट मिशन लांच करेगा मध्यप्रदेश



अरुण पटेल

लेखक  
सुबह सवेरे के  
प्रबंध संपादक हैं

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एआई समिट 2026 में भाग लेते हुए देश की राजधानी दिल्ली में मध्यप्रदेश पवेलियन का भ्रमण करते हुए स्टार्टअप से लेकर अन्य सेक्टर के प्रदर्शन को देखा और दावा किया कि नवाचार में चुनौती तो होती है लेकिन डरने की बजाय इससे पार होने पर काम करना चाहिए। मध्यप्रदेश जल्द ही एआई स्टेट मिशन लांच करेगा और एआई का सुशासन और विकास के लिए इस्तेमाल करेगा। उनका यह भी मानना है कि धार्मिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है इस भी विचार करेंगे। सिंहस्थ 2028 उच्चैन में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, इस महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण से लेकर लोगों को सुदृढ़ बनाने में भी एआई की मदद लेंगे।

डॉ. यादव का यह भी मानना है कि शिक्षा, बिजली और पर्यटन में एआई के बेहतर उपयोग को लेकर हमारा सर्वाधिक फोकस रहेगा। खासतौर पर कृषि में ज्यादा उत्पादन, फसल की बीमारियों का पता लगाने सहित अन्य बीमारियों पर एआई का उपयोग होगा। हर एक किसान इसका कैसे उपयोग करेगा यह जरूर चुनौती है, लेकिन कृषि विभाग

एआई का कैसा उपयोग करे इस पर विचार हो रहा है। जहां तक डॉ. यादव के दावे का सवाल है उसमें दो-मत नहीं हो सकते कि यदि सरकार चाहेगी तो वह कर सकती है, लेकिन इसके पूर्व उसको किसानों और विभाग में तालमेल बिठाने पर कड़ाई बरतना होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों-मुख्य बनाना होगा ताकि वे सरल भाषा में किसानों को यह समझा सकें कि हम आपके हित में यह कर रहे हैं और किसान भी उसमें सहमत होकर अपनी पूरी सहभागिता करें। मध्यप्रदेश जो कि देश का दिल है की खुबियों का बखान करते हुए डॉ. यादव यह भी फरमाते हैं कि यहां पर ट्रांसपैरेंशन आसान है इसलिए एआई हब बनने की संभावना है और सरकार एआई के निवेश के लिए हरसंभव सहयोग करेगी।

प्रदेश में डाटा सेंटर बनाने की भी काफी संभावना है। जहां तक लाजिस्टिक हब का सवाल है उसमें भी बेहतर डेस्टीनेशन है इसलिए उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में आकर निवेश करने का आह्वान किया है।

मध्यप्रदेश में इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिए आरोप-प्रत्यारोपों की भी झड़ी लगी हुई है

क्योंकि यह ऐसा अवसर होता है जिसमें हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाता है। जहां तक मध्यप्रदेश के भारी-भरकम घाटे का सवाल है उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा यह दावा कर रहे हैं कि सरकार ऋण इसलिए ले रही है



कि वह राज्य के वित्तीय संसाधनों का एक स्रोत है। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप भी मढ़ा कि कांग्रेस सरकार ने ऋण लेकर उस राशि का वेतन और भत्तों में व्यय किया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में जबकि मध्यप्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो ऋण लिया गया उससे

राजस्व घाटे की स्थिति बनी। लेकिन हमारी सरकार ने जो ऋण लिया है उससे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पेयजल व सिंचाई की परियोजनाओं आदि में खर्च किया जा रहा है और उससे अधोसंरचना निर्मित की है जो कि आगे कई वर्षों तक प्रदेश की धरोहर रहेगी और विकास में भी सहायक बनेगी। जहां तक विकास में सहायक बनने का सवाल है उस स्थिति को पूरी तरह से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नौकरशाही पर भी सरकार को कड़ी नजर रखना होगी क्योंकि कभी-कभी वह अच्छी से अच्छी योजना को भी विफल कर देती है। हालांकि पिछले कुछ समय से देखा गया है कि सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। यदि एक बार अधोसंरचना विकसित हो गयी तो फिर प्रदेश की प्रगति में जो पंख लगे उन्हीं कोई चाह कर भी नहीं रोक पायेगा। कोविडकाल की त्रासदी का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री यह भी कहते हैं कि 2019-20 से लेकर 20-21 के कार्यकाल को छोड़ दें तो सरकार निरंतर राजस्व आधिक्य में रही है।

इंफ्रा के लिए ढाई सौ अरब डालर का निवेश- इन दिनों विश्व फलक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बाढ़ आई हुई है। इसमें तेजी से निवेश भी बढ़ रहा है। हालांकि 2025 में इस क्षेत्र में कुल निवेश में भारत की हिस्सेदारी भी रही है। भारत को इंफ्रा स्ट्रक्चर और डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए ढाई सौ अरब डालर के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें इनवेस्टमेंट का वायदा किया गया है उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 110, अदानी समूह के लिए 100, माइक्रो साफ्ट के लिए 50, अमेजन के लिए 35, गूगल के लिए 15.5 और योझा के लिए 2 अरब डालर के निवेश का भरोसा दिलाया गया है। इसकी घोषणा अमेजन ने पिछले साल की थी। भारत भले ही बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर या मेमोरी चिप का निर्माण नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट और इंजीनियरिंग सप्लाय चेन में उसकी प्रभावो मौजूदगी है। विशेषज्ञ एआई बूम से लेकर पावर इक्यूपमेंट, जर्नर और एवीएसी यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मौके देखते हैं। यानी सिर्फ टेक्नालॉजी में नहीं, पूरे इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट साइकल में तेजी आ सकती है।

## जिला जेल के बाहर रील बनाकर वायरल

इंदौर। जिला जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह कोई बड़ी वारदात नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक रील है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने जिला जेल के मुख्य दरवाजे और परिसर के आसपास रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जिला जेल परिसर को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां बिना पूर्व अनुमति फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद वीडियो बनाए जाने और सार्वजनिक रूप से साझा किए जाने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में युवक स्वयं को प्रभावशाली दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच हरकत में आ गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल वीडियो की सत्यता, लोकेशन और संबंधित युवकों की पहचान में जुटी हुई है।

## शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, केस दर्ज

इंदौर। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर छात्र के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छात्र ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती एक युवक से हुई थी, जो मूल रूप से राजस्थान का निवासी है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने शादी का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब छात्र ने विवाह का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

## जुए के अड़े से 23 जुआरी गिरफ्तार

इंदौर। शहर के इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान की छत पर संचालित जुए के अड़े पर छपा मारा। गणेश नगर में सूचना मिलने पर दो थानों की संयुक्त टीम ने दबिश देकर 23 लोगों को ताश पत्तों से जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 5 लाख 5 हजार रुपए नकद और ताश के पत्ते बरामद किए। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। एसीपी विजय सिंह चौधरी ने बताया कि सूचना के आधार पर योजनाबद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

## प्राचीन मंदिर के रास्ते पर अतिक्रमण

इंदौर। धार रोड स्थित जीएनटी मार्केट क्षेत्र में होलकर स्टेट कालीन एक प्राचीन मंदिर के मार्ग को अतिक्रमण रूप से बाधित किए जाने की सूचना पर भारत रक्षा मंच के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। संगठन का आरोप है कि मंदिर के प्रवेश मार्ग पर अतिक्रमण कर रास्ता बंद करने का प्रयास किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी हो रही है। मामले को गंभीर बताते हुए मंच ने पहले एएसडीएम को और उसके बाद महापौर को ज्ञापन सौंपकर मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय पंकज सोलंकी, शरद शेखावत, सुनील शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई गई है।

## अनाथ बच्चों को सांवरिया सेठ की यात्रा

इंदौर। शहर की प्रतिष्ठित संस्था त्रिनेत्रम सामाजिक संगठन ने सेवा कार्यों की परंपरा निभाते हुए कालानी नगर स्थित उन्मुक्त आनंद बाल आश्रम के बच्चों एवं वृद्धाश्रम की माताओं को राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सांवरिया सेठ मंदिर की निःशुल्क धार्मिक यात्रा करवाई। संस्था अध्यक्ष हर्षल चौहान ने बताया कि उपाध्यक्ष सुनील ठाकुर के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष सेवा गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आश्रम संचालिका सौम्या जैन ने संस्था का आभार जताते हुए कहा कि बच्चे इस यात्रा से बेहद उत्साहित हैं। संस्था पिछले 13 वर्षों से निरंतर सामाजिक व धार्मिक सेवा कार्य कर रही है।

## स्वास्थ्य शिविर में 260 मरीज पहुंचे

इंदौर। लसुंडिया परमार में इंदौर सिटी हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं रोग निदान शिविर लगाया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले शिविर में 260 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधीर हक्सर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय कुमार निमाडे, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ डॉ. दिशा दुबे, लेप्रोकोपिक सर्जन डॉ राजीव कनेरिया, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ बीबी त्रिपाठी, अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ तनवीर शेख ने मरीजों का परीक्षण किया। इस दौरान ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बोन डेंसिटी की जांच की गई। यह जानकारी सहायक प्राध्यापक डॉ शरद सिंह लोधी ने दी।

## एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल फिर खुलेगा बढ़ते यात्री दबाव के बीच बड़ा फैसला

व्यस्त समय में भीड़ कम करने की तैयारी, अप्रैल से चरणबद्ध उपयोग

इंदौर। लगातार बढ़ रहे यात्रियों और उड़ानों के दबाव को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर मौजूदा टर्मिनल पर बढ़ते लोड को कम करने के लिए अब पुराने टर्मिनल को दोबारा संचालित करने की योजना बनाई गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन का उद्देश्य व्यस्त समय में लगने वाली लंबी कतारों, चेक-इन काउंटर पर भीड़ और सुरक्षा जांच में आने वाली देरी को नियंत्रित करना है। पुराने टर्मिनल के उपयोग से यात्रियों की एंटी-एग्जिट प्रक्रिया तेज होगी और अलग-अलग समय पर आने-जाने वाली उड़ानों का बेहतर वितरण संभव हो सकेगा। एक अप्रैल से इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि संचालन प्रभावित न हो और यात्रियों को असुविधा भी



## पुराने टर्मिनल का सुधार

एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुराने टर्मिनल से उड़ानों का संचालन करने के लिए सुधार कार्य आरंभ किया गया था। इस कार्य का सिविल वर्क पूरा हो चुका है, अब आंतरिक रिनोवेशन किया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने अप्रैल माह से संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसमें इमिग्रेशन, अग्नि सुरक्षा और अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया शामिल है। संभावना है कि उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इसका लोकार्पण करेंगे। बीते वर्षों में इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज हुई है। ऐसे में पुराने टर्मिनल सुविधा संचालन की स्थिति के लिए आवश्यक मानी जा रही है। पुराने टर्मिनल की वापसी को भविष्य की मांग के अनुरूप त्वरित और व्यावहारिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जिससे सुविधा और क्षमता दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सके।

न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि टर्मिनल क्षमता बढ़ाना केवल भवन विस्तार नहीं, बल्कि यात्री

प्रवाह, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग गेट और बैगेज मूवमेंट का संतुलित प्रबंधन भी है।

## ई-केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी बैंक अफसर बनकर कॉल कर ठगी

फोन नंबर बदलकर बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए

इंदौर। शहर की एक कार कंपनी में डाटा एंटी का काम करने वाले एक कर्मचारी के बैंक खाते से ठगों ने करीब 5 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने खुद को बैंक कर्मि बताकर ई-केवाईसी अपडेट करने के नाम पर कॉल किया था। फोन के बाद आरोपी ने पीड़ित का मोबाइल नंबर बदलवाकर उसके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए रकम निकाल ली। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने पहले साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शनिवार को शिकायत थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। द्वारकापुरी पुलिस ने स्कीम नंबर-71 निवासी विकास पुत्र कैलाश शुक्ला को शिकायत पर दो मोबाइल नंबरों से कॉल करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित विकास एक निजी कार कंपनी में डाटा ऑपरटर के रूप में काम करता है। उसने पुलिस को बताया कि 13 फरवरी की शाम उसे एक व्यक्ति ने राहुल शर्मा नाम बताकर कॉल किया और खुद को बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा कर्मचारी बताया। काम करने वाले ने कहा कि उसके खाते की ई-केवाईसी अपडेट नहीं है।

## मामले की पुलिस जांच शुरू

इसके बाद आरोपी ने एक साॅफ्टवेयर का लिंक मोबाइल पर भेजा, जिसे डाउनलोड करते ही पीड़ित के बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल गया। इसके कुछ ही देर बाद खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 5 लाख रुपए अन्य खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। पीड़ित के मोबाइल पर लगातार ट्रांजेक्शन के मैसेज भी आते रहते। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने पहले साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शनिवार को उसे द्वारकापुरी थाने बुलाया गया, जहां पुलिस ने दोनों मोबाइल नंबरों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कॉल कहां से और किस नेटवर्क के जरिए की गई थी।

## शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण महिला की शिकायत पर दुष्कर्म केस

लिव-इन में रखने को राजी, पर शादी नहीं, पुलिस जांच में जुटी

कराई थी। दूसरे पति की पहली पत्नी का निधन हो चुका था और उसके दो बच्चे भी हैं। कुछ समय बाद वह शराब के नशे में पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा। वर्ष 2021 में दोनों परिवारों की सहमति से पति-पत्नी अलग हो गए थे। कुछ समय तक माता-पिता के पास शिशु में रहने के बाद पीड़िता तुकोगंज क्षेत्र में आकर रहने लगी। यहीं काम के सिलसिले में वर्ष 2022 में उसकी पहचान विराज देसाई से हुई। पीड़िता के अनुसार, विराज ने एक दिन उससे कहा कि वह उसे पसंद करता है और बाद में उसे मालवा मिल इलाके में किराए का मकान दिलाया। यहां उसने जल्द शादी करने का भरोसा दिया और बाद में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। इंकार करने पर



इंदौर। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदान केंद्रों की नई तस्वीर साफ हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में केंद्रों का पुनर्गठन पूरा कर लिया गया है। अब इंदौर के 1443 भवनों में कुल 3210 मतदान केंद्र संचालित किए जाएंगे। प्रशासन ने इस बार सुगम और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए 248 नए सरकारी और निजी भवनों को भी चिह्नित किया है। पुनर्गठन के नए आंकड़ों के मुताबिक, जिले के शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का घनत्व अधिक है। कुल 3210 केंद्रों में से 2316 केंद्र शहरी इलाकों में बनाए गए हैं, जो 1045 भवनों में स्थित होंगे। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 398 भवनों में 904 मतदान केंद्र तय किए गए हैं। निर्वाचन मानकों के आधार पर एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1600 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है, ताकि वोटिंग के दिन केंद्रों पर अत्यधिक भीड़ न हो और मतदाताओं को लंबी लाइनों से राहत मिल सके।

प्रशासनिक सर्वे में यह भी सामने आया है कि जिले के 633 भवन ऐसे हैं, जहां एक से अधिक बूथ संचालित होंगे। इनमें से 188 भवनों में दो-दो, 185 भवनों में तीन-तीन

घर के नजदीक ही व्यवस्थित मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में अब इन केंद्रों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है।

## शहरी और ग्रामीण केंद्रों का बंटवारा

इंदौर जिले में मतदाताओं का घनत्व काफी संतुलित है। जिले में 3126 केंद्र ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 301 से 1100 के बीच है। जिले में एक भी ऐसा केंद्र नहीं है जहां मतदाताओं की संख्या 300 से कम हो। शहरी क्षेत्रों में 1045 भवनों में 2316 मतदान केंद्र होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में 398 भवनों में 904 मतदान केंद्र बनेंगे। एक केंद्र पर अधिकतम 1600 मतदाता होंगे। 20 भवन ऐसे होंगे जहां 6 से ज्यादा मतदान केंद्र होंगे। इंदौर में कई ऐसे बड़े परिसर हैं, जहां एक ही छत के नीचे कई मतदान केंद्र होंगे। 633 भवन ऐसे हैं, जहां एक से ज्यादा केंद्र होंगे। 188 भवनों में 2-2 केंद्र होंगे। 60 भवनों में मतदान केंद्र संचालित होंगे। 20 भवन जो बड़े केंद्र हैं, वहां 6 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। 300 से कम मतदाताओं वाला एक भी केंद्र नहीं होगा।

## जिसे बच्चा चोर समझा वो मानसिक विक्षिप्त

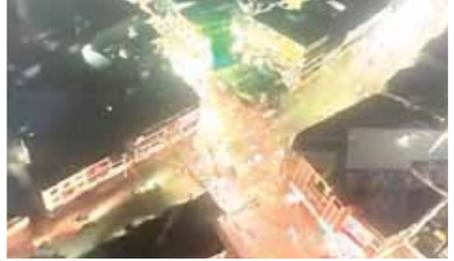
इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के कारण महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पीटा और बाद में पुलिस से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि महिला डेढ़ साल से लापता थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीडियो के आधार पर शिव, राजेश, प्रशांत सहित तीन महिलाओं शिला, ज्योति और संगीता को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि अफवाह के कारण वह घटना हुई। आरोपियों से पूछताछ जारी है और लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें।

## राजवाड़ा क्षेत्र में ड्रोन से ट्रैफिक मैनेजमेंट व सर्विलांस कार्यवाही

पुलिस की डिजिटल निगरानी, नियम उल्लंघन पर सख्ती

इंदौर। शहर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 22 फरवरी को रात 9 बजे राजवाड़ा क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं सर्विलांस की विशेष कार्यवाही की गई। विजयनगर, एमआईजी सहित राजवाड़ा क्षेत्र, जो शहर का अत्यंत व्यस्त बाजार क्षेत्र है, वहां हाई-रेजोल्यूशन ड्रोन कैमरों के माध्यम से डिजिटल पेट्रोलिंग कर यातायात व्यवस्था की निगरानी की गई। ड्रोन से प्राप्त लाइव फुटेज को कंट्रोल रूम में मॉनिटर कर अधिकारियों द्वारा मौके पर तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। शहर में डिजिटल



## चिह्नित उल्लंघन

- नो पार्किंग में वाहन खड़े कर यातायात बाधित करना।
- रॉन्ग साइड वाहन संचालन।
- लेफ्ट टर्न बाधित करना।
- दुकानों के सामने अनावश्यक भीड़ एकत्रित कर मार्ग अवरुद्ध करना।
- चिह्नित किए गए वाहन चालकों के विरुद्ध मौके पर पेट्रोलिंग टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

निगरानी प्रणाली सक्रिय है एवं ड्रोन फुटेज के आधार पर नियम उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध

कार्यवाही जारी है। सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था के लिए सहयोग करें।

## संपादकीय

## भारत-ब्राजील में अहम समझौता

भारत और ब्राजील के बीच दुर्लभ खनिज रक्षा क्षेत्र में हुए 20 अरब डॉलर के करार के साथ-साथ और भी कई समझौते दोनों देशों के बीच दृढ़ होते रहिते और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न्यूते पर चार दिनों दौरे पर भारत आए थे। इस दर्मिणन ये समझौते हुए। गौरतलब है कि ब्राजील लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और नियोबियम जैसे खनिजों का विश्व के प्रमुख उत्पादकों में है। भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता 218 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है और आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा की मौजूदगी में भारत और ब्राजील ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साथ ही इस्पात आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती, सामरिक स्वावलंबन और आर्थिक शक्ति के नए युग की घोषणा है। इसी संदर्भ में ब्राजील के सरकारी बैंक बैंको डो ब्राजील की अध्यक्ष टारसियाना मेडेरोस ने कहा है कि उनका बैंक भारत-ब्राजील व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने में रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आयोजित भारत-ब्राजील बिजनेस फोरम में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अभी और बहुत संभावना है। उन्होंने कहा कि कृषि, ऊर्जा, खनिज, दवा, तकनीक और मैनुफैक्चरिंग ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सहयोग बढ़ाकर व्यापार को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। समझौते के बाद साझा प्रैत वार्ता को संबोधित करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'मेरे प्यारे दोस्त' बताते हुए कहा कि हम दोनों सिर्फ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं हैं। यह एक डिजिटल सुपरपावर और एक रिन्यूएबल एनर्जी सुपरपावर की मीटिंग है। पीपुम मोदी ने कहा कि ब्राजील ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोएलिशन की को-चेयर करने का भी प्रस्ताव दिया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। हम अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ समझौता मजबूत और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उल्लेखनीय है कि ब्राजील लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और नियोबियम जैसे खनिजों का विश्व के प्रमुख उत्पादकों में है। भारत को इस्पात उत्पादन क्षमता 218 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है और आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स समझौता केवल उद्योग की जरूरत नहीं, बल्कि सामरिक आवश्यकता है। विश्व में रेयर अर्थ उत्पादन पर चीन का लगभग एकाधिकार रहा है। भारत लंबे समय से निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। संदेश स्पष्ट है कि भारत अपने औद्योगिक और सामरिक भविष्य को किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं छोड़ेगा। इस साझेदारी से भारत को कच्चे माल की सुरक्षा, नई तकनीक, निवेश और बाजार मिलेगा। ब्राजील को भारत की तकनीकी दक्षता, औषधि आपूर्ति, डिजिटल ढांचा और विशाल उपभोक्ता बाजार का लाभ मिलेगा। यह समझौता एक रणनीतिक घोषणा है कि भारत जहां अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है, वहीं किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। यह समझौता अमेरिका और चीन के लिए भी बड़ा संदेश है।

## लैंगिक समानता की ओर न्यायपालिका का आत्ममंथन



य केवल विधि की धाराओं में सीमित शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि समाज की आत्मा में बसने वाला विश्वास है। जब कोई पीड़ित अन्याय की अधेरी सुरंग से गुजरता है, तो उसे अदालत की चौखट पर ही उम्मीद की पहली किरण दिखाई देती है। विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में न्याय की संवेदनशीलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि निर्णय की भाषा में करुणा और दृष्टि में निष्पक्षता न हो, तो न्याय अधूरा रह जाता है। अदालतें संविधान की मर्यादा, निष्पक्षता और इस विश्वास का प्रतीक हैं कि कानून का शासन किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या प्रभाव से ऊपर रहेगा। न्यायाधीशों पर यह गंभीर दायित्व होता है कि वे कानून की सही व्याख्या करें, उसे इमानदारी से लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित को न्याय मिले। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय करें। किंतु हाल के वर्षों में विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े कुछ मामलों में न्यायालयों की कुछ टिप्पणियाँ और फैसले सार्वजनिक चर्चा और चिंता का विषय बने हैं। इन घटनाओं ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि कहीं न्यायिक सोच में अनजाने पूर्वाग्रह, पितृसत्तात्मक धारणाएँ या लैंगिक संवेदनशीलता को कमी तो प्रभाव नहीं डाल रही। इस बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका के भीतर अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, विशेषकर यौन हिंसा और लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों में। सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक महत्वपूर्ण संख को सामने लाती है कि न्याय केवल कानून की धाराओं को यांत्रिक ढंग से लागू कर देने से नहीं मिलता। न्याय इस बात पर भी निर्भर करता है कि न्यायाधीश किस दृष्टि से मामले को देखते हैं, किस भाषा का प्रयोग करते हैं और किस संवेदना के साथ निर्णय देते हैं। जब अदालतें यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा जैसे मामलों में कानून की व्याख्या करती हैं, तब उनके शब्द केवल कानूनी टिप्पणी नहीं होते, बल्कि उनका सामाजिक और नैतिक प्रभाव भी गहरा होता है। न्यायालय की एक अस्वेदनशील टिप्पणी समाज में प्रचलित गलत धारणाओं को मजबूत कर सकती है, पीड़िताओं को न्याय मांगने से हतोत्साहित कर सकती है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम कर सकती है।

इसके विपरीत यदि न्यायिक दृष्टिकोण सहन्युतपूर्ण और समझ से भरा हो, तो वह संस्थाओं में विश्वास बढ़ाता है और पीड़िता की गरिमा को सम्मान देता है। इसी उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को निर्देश दिया है कि वह विशेषज्ञ समिति गठित कर ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करे, जो न्यायाधीशों में यौन हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और सहन्युत विकसित कर सकें।

ऐसी पहल की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि न्यायिक भाषा और तर्क में कई बार पितृसत्तात्मक सोच और पुराने सामाजिक पूर्वाग्रह झलकते रहे हैं। वर्ष 2023 में एक पुस्तिका भी तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को यह समझाना था कि वे अपनी भाषा में छिपी रूढ़िवादी और स्त्री-विरोधी अभिव्यक्तियों को पहचानें और उनसे बचे। इस पुस्तिका का मकसद यह था कि अदालतें



ऐसा मंच न बनें, जहाँ पीड़िताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराया जा या उन्हें शर्मिंदा किया जाए। हालांकि यह प्रयास सराहनीय था, लेकिन उसका व्यापक और ठोस प्रभाव अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। समय-समय पर ऐसी टिप्पणियाँ सामने आती रही हैं, जिनमें यौन हिंसा को हल्का कर देखा गया या पीड़िता के चरित्र पर प्रसन्नचिह्न लगाए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल दस्तावेज तैयार कर देने से बर्लाव नहीं आता, बल्कि निरंतर प्रशिक्षण, जागरूकता और संस्थागत सुधार की आवश्यकता होती है। लैंगिक हिंसा से जुड़े मामले इसलिए भी जटिल होते हैं क्योंकि वे एक ऐसे सामाजिक ढाँचे के भीतर घटित होते हैं, जो लंबे समय से पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित रहा है। भारत सहित अनेक समाजों में महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर कई प्रकार की असमानताओं का सामना करती हैं। उनकी स्वतंत्रता पर अटकड़े बंधन लगाए जाते हैं और उनसे विशेष प्रकार के

व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यदि न्यायिक निर्णय देते समय इन सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में न रखा जाए, तो कानून की व्याख्या अनजाने में समाज की प्रचलित मानसिकता को ही दोहरा सकती है, जबकि अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान के मूल्यों समानता, गरिमा और न्याय, के आधार पर निर्णय दें। यह भी सच है कि न्यायाधीश भी उसी समाज का हिस्सा होते हैं, जहाँ ये पूर्वाग्रह मौजूद हैं। इसलिए यदि वे स्वयं सजग प्रयास न करें और उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण न मिले, तो ये पूर्वाग्रह अनजाने में उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

अब वक्त आ गया है कि हम यह समझें कि न्यायिक संवेदनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि कानूनी मानकों से समझौता किया जाए या साक्ष्यों की कसौटी को ढीला किया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि न्यायाधीश पीड़िता की मनोवैज्ञानिक स्थिति, उसके सामाजिक परिवेश और उसके

सामने मौजूद चुनौतियों को समझें। उदाहरण के लिए, कई बार यौन हिंसा की शिका महिलाएँ सामाजिक बदनामी, भय या अविश्वास के कारण तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करती। यदि अदालतें इस तरीके को झूठ का संकेत मान लें, तो वे उस मानसिक आघात और सामाजिक दबाव को नजरअंदाज कर देंगी, जिनसे पीड़िता गुजरती है। इसी तरह पीड़िता के पहनावे या उसके निजी जीवन पर प्रश्न उठाना उन रूढ़ियों को बढ़ावा देता है, जो अपराध की जिम्मेदारी को आरोपी से हटाकर पीड़िता पर डाल देती हैं। एक संवेदनशील न्यायिक दृष्टिकोण इस बात को सुनिश्चित करता है कि निर्णय का केंद्र आरोपी की कार्रवाई और कानून के प्रावधान हों, न कि पीड़िता के चरित्र पर नैतिक टिप्पणी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशिक्षण और दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर दिया गया जोर समय की मांग है। लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम को बल्लते कानूनी मानकों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों और मनोविज्ञान के नवीन अध्ययनों से परिचित करा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और विधि विशेषज्ञों द्वारा संचालित कार्यशालाएँ न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को बल्लते बना सकती हैं और उन्हें आत्ममंथन के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ऐसे प्रशिक्षण को किसी की क्षमता पर प्रसन्नचिह्न के रूप में नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की मजबूती के निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।

## पूँजी, प्रकृति और नीति, जलवायु न्याय की तलाश

## सड़क के गड्ढे की आत्मकथा



यार्करण के साथ पूँजी के संबंध मामले में पहले की तमाम बुराइयाँ आज उन क्षेत्रों में प्रकट हो गयी हैं जिन्हें आमतौर पर 'पर्यावरण संकट' कहते हैं, जिसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन सतह का ध्वंस, ज्वलकटिबन्ध के जंगलों का विनाश, मछलियों का बेतहशा मरना, प्रजातियों का विलोप,जैव विविधता का नुकसान, वायुमल और भोजन में अभाव जह,मस्त्रस्त्रलीकरण, जलपूति का सिकुड़ना, साफ पानी का घुलता जहर,मस्त्रस्त्रलीकरण, जलपूति का सिकुड़ना, साफ पानी का अभाव और रेडियो एक्टिव प्रदूषण शामिल हैं। इसलिए पर्यावरण संबंधी जिन दशाओं के मानव समाज पर सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं,उनको लेकर आर्थिक विकास की योजना इस तरह बनाने की जरूरत होती है ताकि उसमें जल संसाधन और उनके विस्तार, साफ पानी की उपलब्धता, संसाधनों का वितरण और संरक्षण, कचरे का निबटारा तथा आबादी और औद्योगिक परियोजना के लिए चुने गये विशेष स्थान से संबंधित पर्यावरण प्रभाव जैसे कारकों को देखते हुए बजट बनाना ज्यादा प्रासंगिक है।

बजट केवल आंकड़े और योजनाएँ प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि वे विकास की एक गहरी अवधारणा को भी प्रतिबिंबित करती हैं कि विकास क्या है और देश आर्थिक वृद्धि कैसे हासिल करना चाहता है। बजट आर्टन इस बात को दर्शाता है कि कितने चीजों को महत्व दिया जाता है, किसके हितों की रक्षा की जाती है और विकास की पारिस्थितिकी लागत कौन वहन करता है। ऐसे समय में जब जलवायु संकट, पर्यावरण का क्षरण और सामाजिक असमानताएँ बढ़ती जा रही हैं, बजट का पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करना आवश्यक है। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दो ऐसे लक्ष्य हैं जिनका संतुलन रखना आज सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। विकास कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि पर जोर देना आवश्यक है, परंतु इसके साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्रीय राज्य है, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि, वन एवं खनिज संसाधनों पर आधारित है। राज्य में सूखा, अनियमित

मानसून, बाढ़, हीट वेव और जंगल में आग जैसी घटनाएँ जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष संकेत हैं। अतः 2026-27 का बजट केवल आर्थिक दस्तावेज न होकर जलवायु-जोषिम प्रबंधन का नीति-पत्र भी होना चाहिए था। मध्यप्रदेश सरकार ने 2026-27 का 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।पर्यावरण संरक्षण के लिए मात्र 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 39 करोड़ रुपए से लगभग 20 प्रतिशत कम है। बजट में सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा निवेश, ई-वाहन प्रोत्साहन जैसे उपायों पर जोर है।परंतु सूखा-प्रबंधन, वर्षा जल-संचयन, जलग्रहण विकास, जल-संरक्षण आधारित कृषि, और जलवायु-लचीली फसलों पर व्यय तुलनात्मक रूप से कम दिखाता है। जबकि राज्य की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। जलवायु जोखिमों के अंतर्गत बुदेलखंड में सूखा, नर्मदा-घाटी में बाढ़,आदिवासी क्षेत्रों में वन क्षरण के अनुभार बजट में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

बजट में वनीकरण, कैपा फंड उपयोग और वन्यजीव संरक्षण के प्रावधान तो हैं, लेकिन सामुदायिक वन प्रबंधन और ग्राम सभा आधारित संरक्षण पर अपेक्षा जोर नहीं है। वन और अवसंरचना परियोजनाओं को दी गई प्राथमिकता वनों पर दबाव बढ़ाएंगी। विकास प्रधान मॉडल और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन स्पष्ट नहीं दिखाता है।नर्मदा, ताप्ती, बेतवा जैसी नदियों के पुनर्जीवन कार्यक्रमों की घोषणा कारगरात्मक पहल है। परंतु बड़े बांधों और नहर परियोजनाओं पर अधिक खर्च, छोटे जल-संरक्षण मॉडल जैसे तालाब, चेक-डैम, परंपरागत जल संरचनाएँ की तुलना में ज्यादा है। विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन के बजाय केंद्रीकृत ढांचे पर निर्भरता जलवायु लचीलपान कम कर सकती है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए विशेष बजटीय संरक्षण का अभाव है। बजट में स्मारक विंटी और शहरी अवसंरचना पर व्यय है, परंतु शहरी हरित क्षेत्र, जल निकासी सुधार और हीट एक्शन प्लान के लिए पृथक आवंटन स्पष्ट नहीं है। जब प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसम की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में बढ़ते तापमान के कारण 2050 तक गेहूँ उत्पादन में 6 से 23 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है। 2023 की तुलना में 2024 में गेहूँ उत्पादन 33 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई, जो भारत में सबसे अधिक है। इसे निर्विजित करने के लिए प्राभावी और ठोस कार्ययोजना का बजट में अभाव है।

दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लगभग 3,759.46 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है। पर विशेषज्ञों के अनुसार यह अभी भी भारत के विशाल पर्यावरणीय जोखिमों

और आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बजट बुनियादी जीवाश्म ईंधन, खनन, और पारंपरिक अवसंरचना पर बजट में भारी ध्यान है, जबकि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी लागतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। उच्च-कार्बन उद्योगों से आर्थिक निर्भरता हटाने में बजट कदम पर्याप्त नहीं है और अभी भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर भारी निवेश हो रहा है। बजट का एक बड़ा हिस्सा 'बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर' पर केंद्रित है,यानी राजमार्गों, शहरों, बंदरगाहों और अन्य बड़े ढांचागत परियोजनाओं पर भारी खर्च करने का है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार सृजित करने में बजट अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। लेकिन जो बात अक्सर छूट जाती है, या जानबूझकर उल्लेख नहीं की जाती है। वह है इन परियोजनाओं का पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव। केंद्र की आर्थिक संवेक्षण में कहा गया कि विकास परियोजनाओं के लिए वन स्वीकृतियाँ एक बाधा है, जबकि व्यवहार में सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ अक्सर तेजी से दी जाती हैं।

कुल मिलाकर, बजट ने अवसंरचना को इस तरह बढ़ावा दिया मानो उसके पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभाव महत्वहीन हैं। जब जंगलों की बाधा के रूप में देखा जाता है, जब सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के बजाय लजरी ट्रेनों पर जोर दिया जाता है और जब समुद्री तटों को निजी कंपनियों को सौंप दी जाती हैं, तब हम केवल निर्माण नहीं कर रहे होते हैं बल्कि हम पर्यावरण और समुदायों को जोखिम में डाल रहे होते हैं। आर्थिक संरक्षण ने यह संकल्पना प्रोत्साहित की है कि विकास 37 प्रतिशत शहरी आबादी को सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, लेकिन बजट में इसे सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं दिखाता है। शहरों की कल्पना कारों और हवाई अड्डों से भरे भविष्य के रूप में की जा रही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियानिकी संस्थान (सी) नागपुर ने अपने अध्ययन में बताया है कि देश की 30 प्रतिशत भूमि में उत्पादकता समाप्त हो गई है।

इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए निवेश की जरूरत है। जबकि कृषि बजट उर्वरक सब्सिडी पर केंद्रित रहता है। स्वस्थ भूमि संपन्न अर्थव्यवस्थाओं का आधार है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधा से अधिक हिस्सा प्रकृति पर निर्भर है। फिर भी हम इस प्राकृतिक पूंजी को खतरनाक दर से नष्ट कर रहे हैं। इससे जैव विविधता का नुकसान होता है, सूखे का खतरा बढ़ता है और समुदाय विस्थापित होते हैं। मस्त्रस्त्रलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। जलवायु संकट से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति प्रस्तुत नहीं करता है। सरकार को चाहिए कि वह एक स्पष्ट बजट लाइन, समर्पित वित्तीय रणनीति और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करे, ताकि जलवायु कार्ययोजनाओं को प्राभावी ढंग से लागू किया जा सके और कमजोर समुदायों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।



से मनुष्य जीवन में जन्म के साथ मृत्यु और सुख के साथ दुःख जुड़े हुए हैं, वेसे ही सपट चिकनी सड़क के साथ गड्ढे भी जुड़े हुए हैं। हर शहर के सड़क की आत्मा में गड्ढे अनुभूत स्थिति पाकर सहज ही स्थान पा लेते हैं। जैसे वाटिका में रंग बिरंगी फूल अपने होने को गौरवान्वित समझते हैं, वेसे ही गड्ढे भी अपने को चिकनी सपट सड़क पर गौरवान्वित समझते हैं।

लेकिन सड़क के गड्ढे अपना जीवन सुख शांति से नहीं गुजारना चाहें। समय पर वह अपनी प्रभावी उपस्थिति जताने के लिए लोहों को हड्डी पसली तोड़कर रख देते हैं।इतना ही नहीं कभी तो वह इतनी शक्ति ढंग से व्यक्तिके यात्रा में जुड़े रहते हैं कि उसे घायल कर उसके जीवन को ही बेकूट धाम फूट देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही झील किनारे की एक सुनसान सी रहने वाली सड़क के गड्ढे ने इतना कहर बरपाया कि एक मोटरसाईकल सवार पति-पत्नी और उनके पुत्र न सिर्फ घायल हुए पति और बच्चे की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बेचारी पत्नी चीखती चिल्लाती रही। उसका हरा भरा जीवन रेंगिरस्तान की तरह सूखा वीरान होकर रह गया। तीन दिन पछे एक तेज स्पीड कार रॉटर के समय अचानक इसी गड्ढे के सामने आने और फिर इससे बचने के चक्कर में पलट गई। कार सवार बुरी तरह घायल बचने।

गड्ढों की हिंसात्मक खबरें सुनकर मैंने अपने अखबार के लिए उसे बातचीत करने का मन बनाया। मैं एक दिन शाम के समय वकूटी से उस रोड की ओर ही घूमने निकल गया। मैं जब पहुंचा तो उस समय वहां लोगों की आवाजही नहीं के बराबर थी। मैंने अपनी स्कूटी उस गड्ढे के दूर सड़क किनारे खड़ी की और पेन डायरी लेकर उसके पास पहुंच गया। गड्ढे मुझे देख इस तरह बोलता जैसे उसे पता हो कि मैं प्रकट हूं और वह जैसे अपनी बात कहने के लिए तैयार बैठे हो। मैंने पूछा 'तुम्हारा चिकनी सपट सड़क पर होना तुम्हें बुरा नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे मोत खाने-खाते नीम के पतियों चबाली हो या सफेद दीवार पर काली रेखा खींची हो।' वह बोला

'अब तुम्हें मेरे बारे में जो संभावित जानकारी चाहिए उसे आगे होकर मैं ही बता देता हूं।' लगा जैसे गड्ढा प्रकराओं के प्रश्नों के उत्तर देने में माहिर हो। उसने अपनी बात कहना शुरू किया। 'मेरे आदत दूसरों की खुशी में कोई रखावट डालने की नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं? मुझे सड़क पर सामने तो घात होता है। कभी तेज गति की कार सड़क के सब जगह के चिकनी होने के धम में जब अचानक मुझे देखती हैं तो तेजी से ब्रेक लगाते हैं। इसके चलते संतुलन बिगड़ने से कार फलटी मार लेती है। फिर क्या कुछ अभिय होगा पछुता हूँ। कभी तो लोग घायल हो जाते हैं। कभी लोग मार जाते हैं और कभी कार में आग लग जाती है। मैं सच में दुखी हूं। मुझे हत्याएं होना का तमाम लोगों द्वारा पहना दिया जाता है। पर इन सबके लिए मैं बिल्कुल भी गुनहागार नहीं हूं। जब मेरी जन्मदात्री, सड़क मां का निर्माण ही घंटिया माल लगाकर हुआ है तो बताओ मैं ऐसे में सड़क या मुझे दोष देना कहां तक उचित है? जिम्मेदार लोगों ने कमीशन के चक्कर में कोई ध्यान न देकर, सब कुछ केदार के भरोसे छोड़ दिया। सड़क निर्माण कार्य को ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। उसे तो बस ऐसा आनंद आगया, जैसे मामा के घर में मां परसेने वाली मिल जाए। मेरी क्षमता अधिक भार सहने की नहीं है।

इसलिए जहां में थोड़ी अधिक कमजोर होती हूं वहीं मेरा जन्म होने लगाता है। और फिर रही सही कसर बाँधना पूरा कर देती हूँ। पानी भरने लगता है। मेरा आकार धीरे-धीरे विस्तारित होने लगता है।

'जब कभी लोग मेरी ट्रेट फूट की शिकायत करते हैं तो जिम्मेदार किभाग मेरे ऊपर डामर रेत मिट्टी से लौपातोती करके अपनी जिम्मेदारी पूरा कर देता है। जबकि इस पंचवर्क में भी वही घंटिया सामग्री लोहा दी जाती है।इसलिए कुछ ही दिनों में इस श्रट काम की पोल खुल जाती है।'

'प्रकार महोदय! आपने मेरी दुखती नस पर हथ रख, दिल की बात पछी है। इसके लिए आपको धन्यवाद। अब जब मेरी पीड़ अखबार से प्रकाशित होगी तो लोग मुझे दोष न देकर जो मेरे इस आश्रय रूप के लिए जिम्मेदार है, उनके बारे में जता जान सकेंगे।' मैंने गड्ढे से उसकी दिल की बात सुनी और फिर उसका एक फोटो लेकर प्रेस के लिए रवाना हो गया।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रियल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बाँबे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोकिल संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी स्थानीय संपादक हेमंत पाल प्रबंध संपादक रमेश रंजन त्रिपाठी (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा) RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040, Mobile No.: 09893032101 Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।



म्या ने कई थी के 'बोलियो मती।' पर मोड़ा ने कई - 'अम्मा तुम हमसे ऐसो न कओ। एक दफे तो तुमई ने कहानी सुनई थी जाको सार थो- बोलने वारे के तो बेर भी बिक जात है। गूँगे से कोई कछु न खरीदे। सच्ची के राए, जोन बड़ी जंगे पे जानो होए तो बोलने को अन्ध्यास भी होनो चईए।' पप्पू ने कहा। 'भैया, हमने तो जे भी कई थी के जब बोलना बनेई नहीं तो चुप चै जाओ तो वाको समझदारी कहत है। सुनें नई का सबसे भली चुप।' 'पर अम्मा, कोई कछु बोलत है तो हमसे चुप न रहे जात है।' पप्पू बोले। 'तो जरूरी है कि अपन

बोलोई? जंग हसाई होत है वाको का? मोड़ी देखबे गए हते तो सारे घरई की पोल पछी खोल के आ गए। कछु समझ नइया। तुमई ने नई कई की तुमने दसवीं की परीक्षा में नकल करी हती। फिर भी पास नहीं भये। जबकि हमने तो तुमई लइकी वाले के बारवी पास बताओ तो। कमाई किती करत है तो हमने की थी, अच्छी है तो तुमाए मु में कौड़ा पडे, बताए आए कछु ना कमाए। और तुमसे गाने की किनने कई थी। ऐ..!' अम्मा कुछ खीज कर बोली। 'अब तुमने कछु सीखेई नई तो काहे गाना गाए आए। बताए आए के हमाई घर में तानसेन के बब्बा पैदा भए हते। चलो गा लओ तो ठीक, पर सूर मूर तो मिला लेते। न मिलो सुरु तो

कछु बात नई, बोलई सई बोल देते। सबरी भद पैदा दीं। अब तुमाए घर में भलेई तानसेन के बब्बा पैदा हो जाएं,



पर तुम तो तानसेन नई बन पाए न।' अम्मा अब चिढ़ कर बोली थी। - 'अब तुमई देखो, तुम्हारे बब्बा, बिना बोले ही काम कर गए की नई। इते कछु करत जात हो, कछु और कर के

आ जात हो। अब जे बताओ तुम घर से बार बार बाहर काए भाग जाते हो। भाग के कौनों बगीचा में बैठ गए जे

नई, दस लोगन के बीच में खड़े होके अपनेई महतारी बब्बा के बारे में उल्टा सीधा बोल आए। तुम्हें पता है, मोड़ी बारे मना कर गए- ऐसा चम्पूना से कौन ब्याहगे अपनी मोड़ी कह के। खबरदार जो घर के बाहर कदम रक्खे तो।' अम्मा का गुस्सा साफ दिख रह था। ये एक बार नहीं था। घर के सब लोग परेशान, पर पप्पू सीखे तो। किसी ने कहा था- सीखने की उम्र नहीं होती। सीख लो। अच्छी बात ही

बोलना आना चाहिए। अभिव्यक्ति के लिए बोलना जरूरी है और ऐसा थोड़े है कि तुम अकेले ही बोलते रहते। कह रहे हो, बोलने वाले के बेर बिकते हैं।

बताओ अब तक तुमाए किस्तें बेर बिक गये। बिक गये तो पैसा कहीं है। इसी बात पे बब्बा कई बार ठोक चुके हें। दस लोग सुनते तो तो हँसते हैं। पप्पू कहते कुछ है और लोग मतलब कुछ निकाल लेते हैं। चतुर्दाई भी नहीं पर चतुर समझते रहे। लौडे लपटियों को घेर के बैठे रहते हो। जैसे तुम, वैसी तुम्हारी फौजा। कुछ काम की न काज की, नौ मन अनाज की। अरे सब नाम मिटा दओ, हर रोज अपने बाप दादा का मू काला कर रहे। जितना कमया उससे साफ दिख गए। अब छोटे न रहे। पचास के पार जाने की तयारी है। अम्मा की तकलीफ यही है। सोच के बोलने के लिए कितना कहर, कितनों ने कहा, कितनी बार कहा, कि तू बोलने की झोंक में जो आते कि क्या बोल रहे कुछ समझ न पाते। अम्मा ने इस बार साफ चेतावनी दी- अब देखना कछु बोले तो। पप्पू बोले- तुम कुछ भी कछे, मैं तो बोलूंगा।



अनुभव

श्याम बोहरे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

वर्ष 1981 को है नेहरू युवा केन्द्र होशंगाबाद और किशोर भारती के संयुक्त तत्वाधान में जंगल शिविर आयोजित किया। शिविर का उद्देश्य गांव के लोगों के सहयोग से उनके इंधन और दैनिक जीवन में लकड़ी की जरूरतों को उनके ही सहयोग से पूरा कर उन्हें इस मामले में आत्मनिर्भर करना था। दस दिन के इस शिविर में गांव के साथियों के साथ तय हुआ कि उनके उपयोग में आने वाले आने वाली लकड़ी जिन वृक्षों से मिले उनके पौधे लगाए जाएं, गांव वाले इन्हें लगाएं तथा इनकी देखभाल करें, विकसित करें। वे सामूहिक निर्णय से जरूरत के अनुसार आपस में लकड़ी का बंटवारा करेंगे। सत्र एकड़ जमीन में पौधे लगाए जाएंगे। सब कुछ तय होने के बाद पत्नियां पिपरिया गांव के 40 साथियों के साथ शिविर के पहले तैयारी बैठक हुई। भोजन की व्यवस्था शिविर में ही थी। हम गांव के जातिगत समीकरणों से अधिक परिचित नहीं थे मतलब यह कि गांव में काम करने का दंभ भरने के बावजूद हम गांव समाज को अधिक नहीं जानते थे। इसलिये हमें सब कुछ सामान्य लग रहा था। जब भोजन व्यवस्था का मामला आया तो बताया गया कि किस जाति के सदस्य भोजन पका सकते हैं? कौन परोस सकता है? कौन पका हुआ भोजन नहीं छू सकता है? किसके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पियेंगे? इतना ही नहीं भोजन करने कौन, कहाँ बैठ सकता है, कौन किसके पास नहीं बैठेगा, कौन कितनी संधि देकर मतलब कितनी दूरी पर बैठेगा, आदि आदि। वह समय था जब हम सामाजिक बदलाव के

सपने देखते थे। कबीर, भगत सिंह, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, गांधी की विरासत सहेजने का जुनून सिर पर सवार रहता था। गनीमत थी कि इसके लिए हमें कोई अर्बन नक्सल या टुकड़-टुकड़ें गैंग नहीं कहता था। उस माहौल में जातिगत ऊंच-नीच और भेदभाव की इस व्यवस्था को स्वीकार करना कितना तकलीफदेह रहा होगा आज इस अमृतकाल में अंदाज लगाना कठिन है। कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मन मारकर रणनीति के तहत इस आचार संहिता को स्वीकार कर लिया गया।

शिविर का कार्यक्रम तय हुआ कि सुबह नारते के बाद पौधारोपण के लिए जमीन की सफाई, गड्डे करना, गड्डों में खाद भरना, पौधे लगाना, गड्डों को मिट्टी से पूरना, सिंचाई करना आदि। दो-तीन दिन तो तयशुदा योजना के अनुसार सब कुछ चला। एक दिन बाहर से आए एक साथी, जिन्हें भोजन के संबंध में आचार संहिता की जानकारी नहीं थी, सहज भाव से परोसने लगे। भोजन कर रहे साथियों ने इस आरोप के साथ हंगामा बरपाया कि उनके साथ धोखा करके धर्म भ्रष्ट करने की तरकीब है, जिसे चे मान ही नहीं सकते। भोजन का बाकायदा बहिष्कार किया गया। लगभग दो घंटे की माथापच्ची, आरोप-प्रत्यारोप, मान मनोव्वल और अंत में माफ़ी मांगने के बाद, आचार संहिता और सख्त करते हुए देर रात तक किसी तरह मामला शांत हुआ।

इस घटना के दूसरे दिन सुबह जब काम शुरू हुआ, उसके करीब दो घंटे बाद सभी साथी जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए काम छोड़ कर चले आ रहे थे। हमारा माथा टनका कि रात में मुश्किल से हुई रजामंदी के बाद यह कौन सा नया बखेड़ा खड़ा हो गया? जुलूस के पास आते ही चिंता सुखद आश्चर्य में बदल गई, जब उनका

नारा सुना 'हमारी जाति गरीबी है'

साथियों ने बताया कि हरि भाई ने आज हमारी आंखें खोल दीं। हरि प्रसाद जोशी से पूछा कि यह कैसे हुआ? हरि भाई ने कहा, इन्हीं से पूछो। साथियों ने बताया कि हरि भाई आज बहुत दुखी थे। वे बोले इस शिविर का कोई मतलब नहीं। इसे अभी खत्म कर देते हैं। साथियों ने उनसे पूछा कि रात में सब कुछ निपट तो गया। अब ऐसी बात काहे कर रहे हो? हरि भाई ने तो एक के बाद सवालों की झड़ी लगा दी। हम यह सब किस लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? इससे क्या हो जाएगा? साथियों के यह कहने पर कि संगठन बना कर अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए। क्या तुम्हें नहीं मालूम? हरि भाई ने कहा जब तक हम आपस में बंटे रहेंगे तो संगठन कैसे बनेगा? हम एक साथ बैठकर रोटी तो खा नहीं सकते बड़े आए संगठन बनाने। जातियों में बंटे रहेंगे फिर भी संगठन बना लेंगे।

ग्रामीण सोच-सोच कर एक सवाल का उत्तर दे पाते हरि भाई दूसरा सवाल कर देते। कहते सोचो जरा ये जातियां बनाई किसने? क्यों बनाई? इससे किसको फायदा है? किसको नुकसान है? जब उनसे पूछे तो कहेत खुद सोचो, किसी बात का उत्तर न देते। हम जो भी कहें वे बड़े प्यार से मुस्कराते हुए फिर सवाल कर देते। कुछ भी पूछे बस एक ही बात, सोचो... सोचो। सोच कर बताओ कोशिश करो। यह समस्या हमारी तो है नहीं तो हम इसका हल कैसे बता सकते हैं? कांटा तुम्हारे पांव में लगा है। तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही निकाल सकते हो। कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हारे पांव का कांटा निकालने।

एक साथी ने कहा, हरि भाई ठीक तो कह रहे हैं जो मिलकर नहीं रहते वे धुगतते हैं। धीरे-धीरे बात समझ में

आने लगी। जहां समझ में न आया वहां गाड़ी रुकने लगे। हरि भाई नया सवाल करके थक्का लगा देते। जैसे-जैसे बात समझ में आने लगी, सभी को उसमें रस आने लगा। जब बहुत कुछ साफ हो गया तो हरि भाई ने पूछा, अब बताओ तुम्हारी जात क्या है? लखमन दादा बोले, 'हमारी जात गरीबी है।' यह सुनते ही हरि भाई ने लखमन दादा को गले से लगा लिया। हरि भाई की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आज से लखमन दादा हमारे गुरु। सबने जोश में आकर जोरदार नारे लगाए, हमारी जात गरीबी है, हमारी जात गरीबी है।

किसी ने याद दिलाया कि बहुत हो गई नारेबाजी चलो काम शुरू करो। एक साथ कई साथी बोले, बहुत बड़ा काम हो गया। चलें सभी को खुशखबरी दें और वे नारे लगाते हुए आ गये हम सब को बताने। इससे अधिक सफलता किसी भी कार्यक्रम की और क्या हो सकती है? बड़ी बात यह रही कि शिविर के बाद कई परेशानियों के बावजूद भी साथी अपने फैसले पर डटे रहे। गांव के बाकी लोग जो शिविर में नहीं थे, इस फैसले को आसानी से पचा नहीं पा रहे थे। कई दिनों तक बहस चलती रही। गांव में ही नहीं, आसपास के रिश्तेदारों में भी। लेकिन शिविर में भाग लेने वाले साथी अपनी बात पर डटे रहे। शिविर के बाद उनके संगठन में मजबूती आने लगी। बहुत ही लगन के साथ लगाये गये पौधों की देखरेख की जाने लगी। कुछ साल बाद पौधों के बड़े होने पर काम की कुछ लकड़ी निकाली जाने लगी, जो बहुत ही समझदारी से आपस में बांटी जाने लगी।

जातिगत भेदभाव मिटाने की कई तरह की कोशिशों की जाती हैं। उनका असर भी होता है। जंगल शिविर के इस अनुभव से जो भी सीख मिली उसके सबक जानने

से पहले कुछ बातें जानना जरूरी होगा वर्ना प्रक्रिया का सरलीकरण हो सकता है।

1. किशोर भारती संस्था का वहां 10 साल से ग्रामीण विकास और शिक्षा के काम करते रहना, संस्था के कार्यकर्ताओं की समझदारी, नियत और प्रतिबद्धता में गांव वालों का भरोसा, संस्था द्वारा किये गये कार्यों के लाभ मिलते रहना, जिसके द्वारा आपस में संवाद और भरोसा था।

2. यद्यपि औपचारिक स्तर पर शिविर सरकार के कार्यालय द्वारा आयोजित था, लेकिन गांव वाले उसे किशोर भारती का ही काम समझते थे। यद्यपि मैं भारत सरकार में जिला स्तर का अधिकारी था, लेकिन किशोर भारती से और उनके माध्यम से गांव वालों से मेरे संबंध अनौपचारिक, सरल और दोस्ताना थे। इसका मुझे भरपूर फायदा मिलता रहा। यह मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जिले के 11 विकासखण्डों में काम करता था लेकिन किशोर भारती के प्रभाव क्षेत्र में काम का जो असर था वह दूसरे क्षेत्रों में दूर दूर तक नहीं था। हो भी नहीं सकता था।

सीखे गए सबक को इस तरह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन लंबे समय की प्रक्रिया है, जो कुछ कार्यक्रमों मात्र से शायद न हो। परिवर्तन किसी एक कारण से नहीं होता। अनेकों कारण, काम, घटनाओं और सामाजिक- राजनीतिक परिस्थितियों के मेल से यह हो पाता है। अक्सर कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन कौन कितना टिकाउ होगा और किस वजह से हुआ, यह कहना आसान नहीं है। भरोसा हो तो सतत रूप से गंभीर कोशिश करते रहने से बात बनती है। यह समझना भी जरूरी है कि भरोसा बातों से नहीं काम के नतीजे देखकर होता है।

## समाज का अर्थशास्त्र

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।



विश्व में कई समुदायों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है, जहाँ वंश, संपत्ति और निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं के पास होता है। प्रमुख रूप से जिनमें इंडोनेशिया के मिनांगकाबाऊ, चीन के मोसुओ जनजाति, और भारत के मेघालय की खासी जनजाति भी शामिल हैं। इन समाजों में महिलाएँ परिवार की मुखिया और उत्तराधिकारी होती हैं।

जुटाई जानकारी के अनुसार मिनांगकाबाऊ समाज इंडोनेशिया में है जो दुनिया का सबसे बड़ा मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है, जहाँ संपत्ति महिलाओं द्वारा हस्तांतरित होती है। मोसुओ, चीन (यूना और सिचुआन) के मोसुओ समाज को 'महिलाओं का साम्राज्य' कहा जाता है। यहाँ 'वॉकिंग मैरिज' की परंपरा है। भारत के मेघालय की खासी और गारो जनजातियों में वंशावली माँ के नाम से चलती है और सबसे छोटी बेटी (खतदुह) को संपत्ति विरासत में मिलती है। कोस्टा रिका की ब्रिब्री स्वदेशी जनजाति में महिलाएँ भूमि की मालकिन होती हैं और कबीले के प्रमुख का पद महिलाओं के माध्यम से चलता है। नासो समुदाय को पनामा और कोस्टा रिका में है वह भी खुद को मातृसत्तात्मक बताता है। घाना (अफ्रीका) का आसानते भी एक प्रमुख मातृवंशीय समूह है। घाना गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो पूर्व में टोगो, पश्चिम में कोटे डी इव्वोर, उत्तर में बुरुकिना फासो, और दक्षिण में गिनी की खाड़ी से घिरा हुआ है। घाना की राजधानी अकरा है, और यह देश की सबसे बड़ा शहर भी है।

पिछले दिनों हमने यूट्यूब पर एक टैबलर के वीडियो में घाना के एक ऐसे बाजार को नजदीक से देखा जहाँ बाजार की सारी बागडोर महिलाओं के हाथ में थी। जिन्हें वहाँ मार्केट क्रीन कहा जाता है। मातृसत्तात्मक समाजों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर रहता है और बच्चों का वंश माँ के परिवार से पहचाना जाता है। लेकिन घाना के मातृसत्तात्मक बाजार की मार्केट क्रीन का इनसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। मातृसत्तात्मक समाजों में, महिलाएँ परिवार और समुदाय के निर्णयों में भूमिका निभाती हैं और संपत्ति की उत्तराधिकारिता भी महिलाओं के माध्यम

# घाना के बाजार : महिला सशक्तिकरण की मिसाल

से होती है। उदाहरण के लिए, भारत की खासी जनजाति और घाना के अकरन समुदाय में महिलाएँ परिवार और समुदाय के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि घाना की मार्केट क्रीन महिलाएँ इन सब के अलावा 'बाजार संचालन' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, न कि मातृसत्तात्मक समाज की विशेषता। ये महिलाएँ बाजार में अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करती हैं।

घाना में 'मार्केट क्रीस' उन वरिष्ठ और प्रभावशाली महिला व्यापारियों को कहा जाता है, जो बाजारों में विभिन्न कर्मांडी समूहों (जैसे टमाटर, मक्का, या याम) का नेतृत्व करती हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में 'ओहेम्मा' भी कहा जाता है। वे बहुत कुशलता से बाजार के विशिष्ट अनुभागों का प्रबंधन करती हैं और व्यापारियों के बीच विवादों को सुलझाती हैं। बाजार में आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ग्रामीण उत्पादकों (किसानों) को शहरी बाजारों से जोड़ने के उपाय करती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये महिलाएँ अक्सर एक अनौपचारिक बैंकिंग प्रणाली के रूप में काम करती हैं, जो छोटे व्यापारियों को ऋण और सहायता प्रदान करती हैं। इस तरह ये महिलाएँ घाना के अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और पारंपरिक रूप से व्यापार को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाती हैं। स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के साथ बातचीत कर बाजार की सुविधाओं (साफ-सफाई, टैक्स आदि) का प्रबंधन करती हैं।

घाना की अर्थव्यवस्था और वहाँ के बाजारों की संरचना दुनिया के सबसे दिलचस्प उदाहरणों में से एक है। यहाँ महिलाओं का वर्चस्व है, यहाँ तक कि बाजार में सिर पर माल ढोने वाली श्रमिक महिलाएँ भी बाजार

के परातों में भारी सामान, अनाज की बोरियाँ और खरीदे गए कपड़े लेकर चलती हैं। इनका जीवन अत्यंत कठिन होता है। वे बहुत ही कम मजदूरी पर काम करती हैं और अक्सर बाजारों के पास खुले में या झोपड़ियों में रहती हैं।

घाना की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में इन महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। मार्केट क्रीस घाना के व्यापार की रणनीतिकार हैं, तो कायायेई उस व्यवस्था की मांसपेशियाँ। इन दोनों के बिना घाना की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था का चलना लगभग असंभव है। घाना की सामाजिक और आर्थिक संरचना में वहाँ की मातृसत्तात्मक व्यवस्था का बड़ा महत्व हो जाता है। यह व्यवस्था न केवल परिवारों को चलाती है, बल्कि वहाँ के विशाल बाजारों के स्वरूप को भी निर्धारित करती है।

घाना की सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठन इन महिलाओं, विशेषकर 'कायायेई' की स्थिति सुधारने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। चूंकि मार्केट क्रीस पहले से ही प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए सरकारी प्रयासों का मुख्य केंद्र बोझ ढोने वाली श्रमिक महिलाएँ ही होती हैं।

कौशल विकास और प्रशिक्षण के अंतर्गत इन महिलाओं को केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर रहने से बचाने के लिए 'कायायेई एम्पावरमेंट प्रोग्राम' शुरू किया है। इसमें उन्हें सिलाई, साबुन बनाना, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसे तकनीकी कौशल सिखाए जाते हैं। ताकि वे बाजारों से निकलकर सम्मानजनक और कम जोखिम वाले व्यवसायों में जा सकें। कायायेई अक्सर खुले आसमान के नीचे या

असुरक्षित बस्तियों में सोती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अकरा और कुमासी जैसे बड़े शहरों में इनके लिए विशेष हॉस्टल का निर्माण शुरू किया है। यहाँ उन्हें सुरक्षित रहने की जगह, पानी और स्वच्छता की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। सरकार इन महिलाओं का 'नेशनल हेल्थ इश्योस स्कीम' में मुफ्त या रियायती दरों पर पंजीकरण करती है ताकि बीमारी की स्थिति में उनका इलाज हो सके। अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी इन महिलाओं को मुख्यधारा की बैंकिंग से जोड़ने के लिए मोबाइल मनी और छोटे बचत खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2017 में घाना सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कायायेई पर लगने वाले 'मार्केट टोल' (प्रतिदिन का कर) को खत्म कर दिया था। इससे उनकी दैनिक आय में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पहले उन्हें अपनी मामूली कमाई का एक हिस्सा नगर पालिका को देना पड़ता था। बाजारों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए 'डे-केयर सेंटर' और स्कूलों में नामांकन की सुविधाएँ दी जा रही हैं, ताकि उनकी अगली पीढ़ी को इस कठिन श्रम चक्र से बाहर निकाला जा सके। घाना में अब कई महिलाएँ 'मार्केट क्रीस' के नेतृत्व में डिजिटल साक्षरता भी सीख रही हैं ताकि वे व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स के जरिए अपने माल का ऑर्डर ले सकें।

घाना के प्रसिद्ध बाजारों (जैसे कि अकरा का मकोला मार्केट) में महिलाओं का वर्चस्व इतना अधिक है कि इसे अक्सर 'मातृसत्तात्मक' आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। वहाँ 'मार्केट क्रीस' न केवल व्यापार बल्कि सामाजिक नियमों को भी नियंत्रित करती हैं।

ऐसे में पुरुषों की भूमिका पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बल्कि वह मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स, भारी श्रम और थोक आपूर्ति तक सीमित होती है। घाना के बाजार में एक अनकहा नियम है: 'महिलाएँ व्यापार का चेहरा हैं, और पुरुष उसकी मांसपेशियाँ (शक्ति) का काम करते हैं।' वहाँ पैसा और बाजार की राजनीति महिलाओं के हाथ में होती है, जबकि पुरुष उन सेवाओं को प्रदान करते हैं जिनके बिना बाजार चल नहीं सकता।

घाना में बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक जीवित प्रयोगशाला है, जहाँ मातृसत्तात्मक मूल्यों ने महिलाओं को 'शक्ति' और 'पूंजी' दोनों दी हैं।

## मुद्दा

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।



विज्ञान के आविष्कार ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक रोज नए-नए आविष्कार कर रहे हैं। इसी में से एक है एआई का आविष्कार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक बनकर उभरी है। यह केवल भविष्य की कल्पना नहीं रही, बल्कि आज की वास्तविकता है, जो उद्योगों की संरचना बदल रही है और शासन-प्रणालियों को नए रूप में ढाल रही है। विश्व स्तर पर आयोजित सम्मेलनों और मंचों पर एआई की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हो रही है। ऐसे समय में भारत जैसे देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। एआई क्रांति भारत के लिए विकास, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व के असाधारण अवसर लेकर आई है, लेकिन इन अवसरों के साथ कई गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिनसे निपटने के लिए दूरदर्शी नीति, सुदृढ़ योजना और नैतिक सजगता आवश्यक है।

वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका उसके तकनीकी कौशल और मजबूत डिजिटल ढांचे को दर्शाती है। देश के पास कुशल इंजीनियरों की बड़ी संख्या, सक्रिय स्टार्टअप संस्कृति और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें हैं। इसी कारण भारत एआई के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, क्योंकि वे इसे एक

बड़े बाजार और नवाचार के केंद्र के रूप में देखती हैं। किंतु यह वैश्विक आकर्षण प्रतिस्पर्धा और दबाव की साथ लाता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह केवल विदेशी तकनीकों का उपभोक्ता न बनकर, स्वयं तकनीक विकसित करने वाला और नवाचार करने वाला देश बने। यदि देश एआई की मूल तकनीकों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा, तो इससे उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक मजबूती प्रभावित हो सकती है।

एआई क्रांति की एक प्रमुख चुनौती स्वदेशी तकनीकी क्षमता का विकास है। एआई प्रणालियों के निर्माण के लिए विशाल डेटा, उन्नत कंप्यूटिंग संसाधन और उच्च स्तरीय शोध की आवश्यकता होती है। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी उच्च क्षमता वाले कंप्यूटिंग संसाधनों और बुनियादी शोध के क्षेत्र में वह अभी अग्रणी देशों से पीछे है। इस अंतर को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश आवश्यक है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना होगा। साथ ही सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जो देश में ही एआई उद्यमों और प्लेटफॉर्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करें।

एक और महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि एआई का विकास भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप हो। भारत भाषाई, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत विविध देश है। पश्चिमी देशों के लिए विकसित एआई मॉडल भारत की बहुभाषी आबादी या ग्रामीण समुदायों की

आवश्यकताओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए एआई समाधान स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और समावेशी होने चाहिए। भाषा मॉडल, डिजिटल सहायक, स्वास्थ्य संबंधी तकनीक और कृषि आधारित समाधान ऐसे डेटा पर आधारित होने चाहिए जो भारत की विविध जनसंख्या को प्रतिबिंबित करते हों। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो एआई असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और गहरा कर सकता है।

एआई के संदर्भ में नैतिक प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डेटा की गोपनीयता, एल्गोरिदमिक पक्षपात, निगरानी और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार जैसी समस्याएँ तेजी से उभर रही हैं। भारत जैसे विशाल और लोकतांत्रिक देश में एआई का दुरुपयोग दूरगामी परिणाम ला सकता है। डीपफेक, स्वचालित प्रचार और पक्षपाती निर्णय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे ठोस नियम बनाए जाएँ जो नवाचार को प्रोत्साहित करें, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करें। डेटा संरक्षण, एल्गोरिदम की स्पष्टता और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था किसी भी व्यापक एआई नीति का हिस्सा होनी चाहिए।

रोजगार पर एआई का प्रभाव भी एक जटिल चुनौती है। एआई आधारित स्वचालन पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र की हों या सेवा क्षेत्र की। यहाँ तक कि कई श्वेत कॉलर पेशे भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। यद्यपि एआई नए रोजगार अवसर भी उत्पन्न करेगा,

जैसे डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स और डिजिटल सेवाओं में, परंतु इस परिवर्तन का प्रभाव सभी वर्गों पर समान रूप से सकारात्मक नहीं होगा। जिन लोगों के पास डिजिटल कौशल नहीं हैं, उन्हें रोजगार संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर कौशल विकास और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे। शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में एआई साक्षरता, कोडिंग, डेटा विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे विषयों को शामिल करना होगा। जीवन भर सीखने की संस्कृति को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना समय की मांग है।

शिक्षा प्रणाली को भी एआई युग के अनुरूप बदलना होगा। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एआई को केवल तकनीकी विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक बहु-विषयक अध्ययन के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें नैतिकता, कानून, समाजशास्त्र और लोक नीति जैसे आयाम भी हों। विद्यार्थियों को एआई की क्षमताओं के साथ-साथ उसकी सीमाओं की भी समझ होनी चाहिए। आरंभिक स्तर से ही शोध और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य की पीढ़ी जिम्मेदारी के साथ एआई का उपयोग कर सके। जन-जागरूकता अभियान भी लोगों को एआई के बारे में सही जानकारी देने और उसे समझदारी से अपनाने में सहायक हो सकते हैं।

स्वास्थ्य, कृषि, शासन और जलवायु प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से भारत को व्यापक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई प्रारंभिक

निदान, व्यक्तिगत उपचार और अस्पताल प्रबंधन में सहायता कर सकता है। कृषि में यह मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन और जोखिम कम करने में मददगार हो सकता है। शासन में डेटा आधारित विश्लेषण से नीतियों की गुणवत्ता और सेवा वितरण की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। किंतु इन क्षेत्रों में एआई का उपयोग सावधानीपूर्वक होना चाहिए। पूरी तरह स्वचालित प्रणालियों पर निर्भरता से बचते हुए मानवीय निगरानी और नैतिक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एआई के दौरे में साइबर सुरक्षा भी एक गंभीर चिंता का विषय है। जैसे-जैसे एआई प्रणालियाँ उन्नत होती जा रही हैं, वैसे-वैसे साइबर हमलों के तरीके भी जटिल होते जा रहे हैं। दुर्भावनापूर्ण तत्व एआई का उपयोग करके डिजिटल ढांचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं या गलत सूचनाएँ फैला सकते हैं। इसलिए मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र, सुरक्षित एआई संरचनाएँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं।

एआई क्रांति भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। देश को ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा जो नवाचार को बढ़ावा दे, लेकिन सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। स्वदेशी तकनीकी विकास, नैतिक शासन, समावेशी नीतियाँ और मानव संसाधन में निवेश यह तय करेंगे कि भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ेगा या बाहरी तकनीकों पर निर्भर रह जाएगा। एआई की सच्ची सफलता तभी होगी जब इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा मानवीय गरिमा की रक्षा हो सके।



## वनमाली

वह अंधेड़ जिल्दसाज सबरे से शाम तक और अंधेरा होने पर दीये की रोशनी में बड़ी रात तक, अपनी छोटी-सी दुकान में अकेला एक फुट लम्बी चटाई पर बैठ किताबों की जिल्दें बाँधा करता। उसकी मोटी व भरी अंगुलियाँ बड़ी उतावली से अनवरत रंग-बिरंगे कागजों वेफ पत्रों में उलझती रहतीं और उसकी धुँधली आँखें नीचे को झुकी काम में व्यस्त रहतीं।

जिल्दसाज का स्वभाव रूखा था व स्वर तीखा। ग्राहकों को अपनी मजूरी वेफ जो दाम वह एक बार बता



देता, उनमें कमी-बेशी न करने को उसे एक जिद-सी थी। लेकिन ग्राहक उसकी इस जिद और रुखाई पर भी उसवेफ यहाँ किताबें डाल जाते, क्योंकि जिल्दसाज वास्तव में किताबों की जिल्द बहुत सुन्दर बाँधता था। किताबों की जिल्द बाँधना ही उसवेफ एकाकी विरक्त जीवन में सत्य था और सत्य ही तो सुन्दर होता है।

एक दिन सबरे जिल्दसाज नित्य की भाँति अपनी दुकान में बैठ काम कर रहा था कि इतने में एक स्त्री उसवेफ सामने आ खड़ी हुई। उसके साथ उसका आठ साल का बालक भी था।

स्त्री ने पूछा "क्यों जिल्दसाज, रहीम की किताब की जिल्द तुम्हीं ने बाँधी है?" जिल्दसाज ने नजर ऊपर की।

रहीम? रहीम कौन? वह किसी रहीम को नहीं जानता। न जानने की उसे जरूरत ही है। यह कैसी पापल स्त्री है। काम की बात क्यों नहीं करती? उसके पास तो काम है। काम को लेकर ही वह जीता है। काम ही उसे सही रास्ते पर ले जा रहा है। उसके पास ऐसी कहीं फुरसत, जो वह किसी से अपना सरोकार जोड़े। जिल्दसाज बोला "मुझे नहीं मालूम। तुम अपना काम बताओ।"

स्त्री जिल्दसाज के रूखे जवाब से झेंप गई। उसने बताया "भाई, रहीम की किताब की जिल्द देखकर मेरा लड़का भी अपनी फटी की जिल्द बाँधने के लिये जिद पकड़े हुए है। यह रही किताब। बताओ, क्या लोगे?"

जिल्दसाज ने स्त्री के हाथ से किताब लेकर उसे उल्टा-

पलटा। तब लापरवाही उसे उसने यह कह दिया "छे आने पैसे होंगे।"

जिल्दसाज के लिये सौदा तय रहा, इससे वह काम में लग गया।

पर स्त्री के पास तो पैसों का सवाल था। वह बोली "भाई, छे आने तो बहुत होते हैं। मैं मेहनत-मजूरी करके पेट पालने वाली कहीं से पाऊँगी? मुझसे तीन आने ले लेना। मैं तुम्हारा बड़ा गुन मानूँगी।"

जिल्दसाज भुनभुना उठा।

उसकी बात को दुलखने वाली यह स्त्री कौन होती है? उसकी बात आज तक किसी ने नहीं दुलखी। हमेशा उसे मुँह माँगि दाम मिले हैं। उसने जो चाह है, वह ग्राहकों ने खुशी से दिया है और क्यों न देगे? वह क्या कोई काम में खोत करता है? तब इस स्त्री का उसकी हेटी करने का क्या मतलब? काम की बात में गुन-एहसान की क्या बात? उसका सम्बन्ध तो इस दुनिया से अब तक लेन-देन रहा है। वह तो वेफवल अपनी मजूरी और चोखे काम को चीन्हाता है। उसे दया और एहसान की बात क्या मालूम?

जिल्दसाज ने बताया "छे आने से मैं एक कौड़ी भी कम नहीं लूँगा।"

स्त्री ने आजिजी की "भाई, खुदा तुम्हें बहुत देगा। तुम्हारी मेहरबानी से मेरे बच्चे का दिल रह जायेगा।"

जिल्दसाज इस बार चिढ़ गया।

खुदा? खुदा को वह क्या जानता है? कुल जमा उसने अपनी दुकान से ही जीने के लिए पूँजी पायी है। रोजगार, किताबें, कागज बस इन्हीं वेफ बीच तो उसकी जिन्दगी के लम्बे-लम्बे बरस कटे हैं। उसने तो कभी नहीं महसूस किया कि इस जिन्दगी को चलाने के लिए खुदा की भी कहीं किसी तरह से जरूरत पड़ती है। तब खुदा क्या खाक मदद करेगा?

जिल्दसाज झलकर बोला "मैं खुदा-उदा की बात नहीं जानता। जब तरे पास पैसे ही नहीं थे, तब तू यहाँ क्यों आयी? जा, सिर न खा। काम करने दे।"

जिल्दसाज फिर किसी किताब के पत्रे ठीक जमाने लगा।

लेकिन इस तरह से डौंट जाने पर भी स्त्री वहीं से नहीं टली और उसका बालक भी उसी तरह घबराहट से अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा रहा। स्त्री कभी काम करते जिल्दसाज को देखती और कभी उसकी निगाह जिल्दसाज की जालों और गर्द से भरी दुकान की दीवारों से टकराती। एकाएक कोई बात उसे सूझ गई।

स्त्री ने सहमते-सहमते पूछा "अच्छ, भाई बाकी बचे तीन आने में मैं तुम्हारी दुकान झाड़-बुहार दूँ और जाले व गर्द साफ कर दूँगी। तब तो तुम मेरे बच्चे की किताब की जिल्द बाँध दोगे?"

जिल्दसाज अब सचमुच असमंजस में पड़ गया। ऐसा गरीब ग्राहक उसकी जिन्दगी में अब तक नहीं गुजरा था। उसने काम छोड़ स्त्री पर निगाह डाली। अचानक

## राजधानी आसपास

## जिल्दसाज

## जिल्दसाज अब भी किताबों की जिल्द बाँधा करता था और अब भी उसके पास ग्राहक आते थे, किन्तु अब न तो वह उतनी सुन्दर जिल्दें बाँधता था और न उसके पास पहले-जैसे ग्राहक आते थे।

उसकी दिल की बस्ती में नमी छा गई। उसने पहली बार स्त्री वेफ दीन और निस्सहाय चेहरे को देखा। उसकी पैरन्तों से भारी ओढ़नी को परखा। लड़के का मासूम और बेबस चेहरा भी उससे छिपा नहीं रहा। जिल्दसाज के अन्तस में आज पहली बार रहम बरस पड़ा।

जिल्दबाज तब अपने को छिपाते हुए बोला- "अच्छ दो किताब। मैं मुफ्त बाँध दूँगा। कल आकर तुम ले जाना।"

जिल्दसाज फिर किताब ले, बिना उस स्त्री और बालक की ओर देखे, झट कागजों की कतरन में कोई चीज खोजते खो गया।

दूसरे दिन वह स्त्री अपने बालक के साथ किताब लेने आई। जिल्दसाज ने किताब निकाल बालक को दे दी।

बालक किताब देख खुशी से नाच उठा। बोला- "इतनी सुन्दर जिल्द तो मैं, रहीम की किताब की भी नहीं बैँधी।"

माँ अपने बच्चे की खुशी में फूल उठी। वह जिल्दसाज से बोली "भाई खुदा तुम्हारी रोजी में बरकत

दे।"

किन्तु जिल्दसाज यह सब कुछ नहीं देख-सुन रहा था। वह इस ध्यान में उलझा था कि इन दो परदेशियों से किसी अनजाने क्षण में उसकी जो पहचान जुड़ गई है, वह क्या यहाँ टूटकर खत्म हो जायेगी? वह अब अपने अकेलेपन से ऊब उठा था। उसके लिए अब जगत का कोई अर्थ हो आया था। उसका मन अब रोजी को ही सब कुछ मानने से इन्कार करने लगा। उसके अन्दर एक निराली प्यास उठ आयी थी। उसे मासूम पड़ रहा था कि वह प्यास किसी से अपना सरोकार जोड़कर ही शांत की जा सकती है।

जब स्त्री बन्दगी करके चलने लगी, तब जिल्दसाज जैसा रूखा आदमी भी खिलक हो उठा। उसने रुकते-रुकते कहा- "तुम कहीं रहती हो?"

स्त्री का जवाब हुआ "इसी मुहल्ले में रहती हूँ। आपकी दुकान से पन्द्रह-बीस घर छोड़कर के।"

"तुम्हारे खाविन्द क्या करते हैं?" जिल्दसाज ये पूछते हुए इशर-उधर झाँक रहा था।

स्त्री ने बताया "मेरे खाविन्द का इन्काल हुए तो चार बरस होने आये।"

"तो तुम गुजर कैसे करती हो?" जिल्दसाज का यह

तीसरा प्रश्न था। स्त्री बोली "मैं बेलें बनाती हूँ, बूटे काढ़ती हूँ और जरी का काम भी कर लेती हूँ। मगर आजकल यह मजूरी भी मुश्किल हो गयी है।" जिल्दसाज न जाने कुछ देर तक क्या सोचता रहा। तब उसने कहा- "तो सुनो। अगर तुम्हें उन्न न हो तो बगल वाला मेरा जो कमरा खाली है, उसमें तुम आकर रह सकती हो। मेरे लिए तुम रसोई बनाना। मैं ऊपर से तुम्हें चार रुपया महीना दूँगा।"

स्त्री एक बारगी इतनी डेर-सी मेहरबानी न सह सकी। उसका सिर कृतज्ञता से भार से झुक गया। वह थोपे स्वर में बोली "शुक्रिया करती हूँ। आपने मुझ गरीब



औरत को उबार लिया।"

आज जब स्त्री और उसका बालक खुश होते हुए घर चले गये, तब जिल्दसाज सूना-सा, खोया-सा, लोगों की आती-जाती भीड़ को देखता अपनी उसी एक फुट चटाई पर सिकुड़ा अकेला बैठा था।

आगे दिन वह स्त्री अपने कपड़े-लत्तों का एक टीन का बक्स, एक बिस्तर तथा दो-चार एन्सुमीनियम वेफ बरतन ले जिल्दसाज के यहाँ चली आयी।

जिल्दसाज की जिन्दगी में एक नया जमाना आया। उसका बर्ताव अब अपने ग्राहकों से रूखा नहीं होता था। वह बड़ी मुलायमी से उनसे पेश आता। दामों वेफ लिए भी वह अब पहले के समान जिद नहीं करता। उनमें कमी-बेशी करके भी वह लोगों की किताबें डाल लेता।

जिल्दसाज जब किताबों की जिल्द बाँधने बैठता, तब वह पहले-जैसा एकाग्र चित्त नहीं रहता। बीच-बीच में वह बच्चे का पाठ सुनता और कभी उसके माँग करने पर उसे रंगीन कागजों की नावें व दवातें बनाकर देता। जिस दिन खेल-तमाशा होता, उस दिन वह बालक को अपने साथ लिवा ले जाकर तरह-तरह के खिलौने व मिठाइयाँ दिला लाता।

शाम को जब वह काम से ऊब जाता, तब दुकान बंद कर देता। मुँह-हाथ धोकर नमाज पढ़ता व झुटपुटे में दुकान वेफ चबूतरे पर बैठ आते-जाते लोगों को देखा करता और न जाने क्या सोचा करता। रात होने पर वह बड़ी चाहे से घर वेफ भीतर रोटी खाने

"अच्छ, तो मैं तुम्हें अब 'गुल' कहकर पुकारूँगा।" जिल्दसाज ने बड़ी संजीदगी से कहा। गुलशन के गोंरे गाल लाल हो गये। सुन्दर बाँकी आँखों में चिन्ता छ गयी। उसने बड़ी धीमी महीन आवाज में कहा "नहीं-नहीं। इस नाम से मेरे खाविन्द मुझे पुकारा करते थे।"

जिल्दसाज वेफ मुँह से निकला "तो?"

स्त्री कभी ऐसे आमने-सामने नहीं हुई थी। बोली "तो क्या?" जिल्दसाज ने इस बार गुलशन की आँखों में आँखें डालकर "तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उस नाम से न पुकारूँ? यह नहीं होने का। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, पागलपन नहीं। बोला, मंजूर है?"

रज्जब की माँ के लिये यह एक समस्या हो गयी। अभी तक, आज तक उसने एक सेविका की भाँति जिल्दसाज को प्रसन्न रखने की कोशिश की थी। उसकी हँसी का अपनी हँसी से उत्तर दिया था। गुलशन ने सफाई दी "मुझे माफ़ी दो। मुझे इन कौटों में न घसीटो। मुझ बेकस को यों ही पड़ी रहने दो।"

जिल्दसाज का जोश गुलशन वेफ जवाब से एकाएक ठंडा पड़ गया, लेकिन तब भी उसवेफ भीतर के स्वर को ठेलते हुए जैसे उसने पूछा- "तो क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहती?"

"नहीं, सो बात नहीं। मैं तुम्हारी दिलोजान से सेवा करूँगी। तुम्हारी हँसी का जवाब हँसी से दूँगी। मगर तुमसे अर्ज है, तुम मुझसे मेरे खाविन्द की याद न छीनो।" गुलशन की सुन्दर आँखों में करुणा बरस रही थी।

जिल्दसाज एकदम टूट गया, लेकिन बज्रते दीपक के क्षणिक आलोक जैसे उजैजित स्वर में वह बोला "अभी तक मैंने इस दुनिया से कुछ नहीं पाया। आज आखिरी मर्तबा तुम्हें प्यार किया है, सो तुम भी मुझे लुकराकर चूर-चूर कर देना चाहती हो। बोला, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी-सी दया का भी अधिकारी नहीं?"

गुलशन बस इतना ही कह सकी "मुझे माफ़ी दो दो।" जिल्दसाज निरुत्तर हो गया।

मिलन के आरम्भ में जिल्दसाज कठोर था और मिलन के अन्त में रज्जब की माँ।

जिल्दसाज अब भी किताबों की जिल्द बाँधा करता था और अब भी उसके पास ग्राहक आते थे, किन्तु अब न तो वह उतनी सुन्दर जिल्दें बाँधता था और न उसके पास पहले-जैसे ग्राहक आते थे।

विश्वमित्र 1934

## आसमान से टपके, पीएमओ में अटके

## बीपी, परिसीमन और विधायक जी का 'कोना'

राज्य शासन के एक 'पुलक रहे' प्रमुख सचिव साहब की मुराद आखिरकार पूरी हो गई। भारी-भरकम विभाग और उस पर 'माननीय' की मैराथन बैठकों ने साहब का माइग्रेन बढ़ा दिया था। माननीय जब भी भोपाल पधारते, समीक्षा के नाम पर



## मोहन का मंत्रालय

## आशीष चौधरी

पूरा दिन ही पी जाते थे। साहब ने अपना दुखड़ा बिरादरी में क्या रोया, सरकार ने सुनी और तबादले का 'मरहम' लगा दिया। पुराने विभाग की फाइलों और बैठकों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन नए विभाग ने 'हवा' निकाल दी है। नया विभाग भी कम वजनी नहीं है, ऊपर से मुसीबत यह कि इसके एक बड़े प्रोजेक्ट की कुंडली सीधे पीएमओ खंगाल रहा है। यानी साहब, 'बैठकों वाले माननीय' से बचकर अब सीधे 'दिल्ली की रडार' पर आ गए हैं। अब इसे रहत कहें या 'कड़ाही से निकलकर चूल्हे में गिरना', यह तो साहब की अगली छुट्टियाँ ही बताएंगी।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अगले चुनाव परिसीमन और महिला आरक्षण के साथे में होंगे, कई सुरमाओं की धड़कन ऊपर-नीचे होने लगा है। सत्ताधारी दल के एक 'बड़बोले' और मुखर विधायक जी पर इसका असर कुछ ज्यादा ही गहरा है। सुना है विधायक जी ने अब पूरे शहर के चक्कर छोड़कर अपनी विधानसभा के एक 'खास इलाके' में तंबू गाड़ दिया है। क्षेत्र इतना बड़ा है कि पैर थक जाए, लेकिन अब विधायक जी को केवल उसी हिस्से से प्रेम उमड़ रहा है जो उन्हें भविष्य में सुरक्षित लग रहा है। विधायक जी के करीबी धीरे से कह रहे हैं- 'महाराज, पूरे समंदर में डूबने से अच्छा है कि इसी टापू पर कब्जा जमा लिया जाए।' यानी अब जनता से ज्यादा 'रेखागणित (ज्यामिति)' पर फोकस है।

## बुखार, बजट और 'बेमिसाल' देवड़ा

विधानसभा का बजट सत्र गर्म है और विपक्ष का पारा भी, लेकिन उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने साबित कर दिया कि 'इच्छाशक्ति' के आगे थर्मामीटर की रीडिंग कोई मायने नहीं रखती। साहब को तेज बुखार था, गला इतना खराब कि शब्द भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सदन में डटे रहे। विपक्ष ने आरोपों के तीर छोड़े तो देवड़ा जी ने ऐसी तुलनात्मक 'सर्जनी' की कि विरोधियों को भी लोहा मानना पड़ा। उनकी इस 'बीमार' मगर 'धारदार' परफॉरमेंस की तारीफ खुद दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय ने भी कर दी। इसे कहते हैं- 'गला बैठ है तो क्या हुआ, विपक्ष को तो चुप बैठ दिया!' अब सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि अगर बिना बुखार के जवाब देते, तो शायद विपक्ष को सदन के बाहर ही शरण लेनी पड़ती।

## निगम-मंडलों की 'वेटिंग लिस्ट' और बेचैन दिल

संगठन में तो नियुक्तियाँ हो गईं, लेकिन 'लाल बत्ती' के तलबगार नेताओं की निगाहें अब भी सूने पड़े निगम-मंडलों पर टिकी हैं। दो दर्जन से ज्यादा कुर्सियाँ धूल खा रही हैं और सरकार है कि 'शुभ मुहूर्त' निकाल ही नहीं पा रही। अब सुगबुगाहट है कि विधानसभा सत्र की थकान उतरते ही नियुक्तियों की 'लॉस्ट्री' खुल सकती है। जो नेता अब तक दिल्ली और भोपाल की परिक्रमा कर रहे थे, वे अब फिर से एक्टिव हो गए हैं। सबको डर है कि कहीं 'आचार संहिता' या 'परिसीमन' के चक्कर में यह रेवडियाँ हाथ से न फिसल जाएं। उम्मीद और बेचैनी के बीच फिलहाल तो यही नारा चल रहा है- 'इंजार्ज की चड़ियाँ लंबी हैं, पर कुर्सी बड़ी चंगी है!'

## ब्यूटीशियन से नशा देकर रेप, धर्म बदलने का दबाव बनाया

## छत्तीसगढ़ की युवती ने भोपाल में 4 पर कराई एफआईआर, बोली- छोटे कपड़े पहनाकर पब ले जाते थे

भोपाल (नप्र)। छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय ब्यूटीशियन ने भोपाल में 3 लोगों के खिलाफ रेप और एक महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की एफआईआर कराई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमरीन, उसकी छोटी बहन आफरीन और उसके दोस्त चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता रविवार रात अपने मामा के साथ बागसेवनिया थाने पहुंची थी। ब्यूटीशियन ने पुलिस को बताया कि 31 दिसंबर 2024 को शाहपुरा स्थित एक होटल में दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। बाद में दोनों साथ रहने लगीं। जनवरी 2025 में वे बागसेवनिया में रहने वाली अमरीन उर्फ माहिरा के पास शिफ्ट हो गईं। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि उसकी सहेली ने अमरीन के कहने पर धर्म परिवर्तन कर उसके भाई से शादी कर ली है। ड्रस की लत लगाने के आरोप भी पीड़िता ने लगाए हैं।

अलग-अलग समय पर कई



बार रेप- पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2025 में अमरीन का करीबी चंदन यादव बहन से मिलाने के बहाने ले गया। उसने धमका कर रेप किया। बदनाम करने की धमकी देकर चुप करा दिया। इसके बाद अलग-अलग समय पर कई बार रेप किया।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे छोटे कपड़े पहनाकर शहर के पब-लाउंड में ले जाया जाता था। अनजान लोगों से मेल-जोल का दबाव बनाया जाता था। इसी दौरान उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला गया। चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया- नवंबर 2025 में

अमरीन उसे गांधी नगर स्थित अब्बास नगर में अपने परिजन से मिलाने ले गईं। आरोप है कि वहाँ अमरीन के भाई बिलाल ने चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में दुर्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे छोटे कपड़े पहनाकर शहर के पब-लाउंड में ले जाया जाता था

अहमदाबाद में भी दुर्कर्म किया- दिसंबर 2025 में अमरीन पीड़िता को निजी काम का हवाला देकर अहमदाबाद ले गईं वहाँ यासिर नामक युवक से मिलवाया। पीड़िता का आरोप है कि वहाँ भी उसके साथ दुर्कर्म किया गया। जनवरी 2026 में वह भोपाल छोड़कर छत्तीसगढ़ अपने मामा के घर चली गईं।

दूसरी पीड़िता से संपर्क के बाद शिकायत- हाल ही में सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान एक अन्य युवती ने भी अमरीन और उसके साथियों पर इसी तरह के आरोप लगाए। इसके बाद पीड़िता भोपाल आई और बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई।

## ऐसे गिने गए जिले के गिद्ध, संख्या 86 से बढ़कर 156 पर पहुंच गई

इंदौर। तीन दिन से चल रही गिद्धों की गणना रविवार को खत्म हो गई। पिछली बार प्रदेशभर में 12 हजार से ज्यादा गिद्ध थे, इस बार इससे ज्यादा मिले। इंदौर वन मंडल में पिछली बार 86 गिद्ध मिले, जो इस बार बढ़कर 156 हो गए। गिद्ध प्रजाति की विशेषता यह है कि जब तक उसे अच्छा तापमान नहीं मिलता, तब तक ये अपने बड़े पंख फैला नहीं सकते और न उड़ सकते हैं। इसके चलते इनकी गिनती अलसुबह की गई। इस बार इंदौर वन मंडल में वन विभाग के अधिकारियों को गिद्धों की गिनती की ट्रेनिंग इंदौर के मास्टर ट्रेनर ने दी। इसके तहत मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार फरवरी के तेज ठंड के तीन दिन 20 से 22 फरवरी चुन लिए गए।

मध्य प्रदेश में 7 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें 4 प्रजातियाँ स्थानीय और 3 प्रजातियाँ प्रवासी होती हैं। ये सर्दियों के बाद वापस लौट जाती हैं। पहला चरण तब किया जाता है, जब सभी प्रजातियों के गिद्ध घोंसले बनाकर अंडे दे चुके होते हैं या नवजात बाहर आ चुके होते हैं। फरवरी तक ये बच्चे उड़ान की तैयारी में होते हैं, इसलिए शीत ऋतु का अंतिम समय गणना के



लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अलसुबह गिद्ध नहीं उड़ते - गिद्धों की गणना ठंड

के दिनों में ही इसलिए होती है, क्योंकि सुबह जब तक इनके उड़ने लायक तापमान नहीं हो जाता तब तक वे

अपने ठिकानों पर ही मिलते हैं। ऐसे में सुबह ही इनकी गिनती की जाती है और यही संख्या सही साबित होती है।

दरअसल, जहाँ गिद्धों की बसेरा ऊंची पहाड़ी, चट्टान, किले आदि वहाँ सुबह 6.30 बजे वन विभाग की टीमें पहुंच गईं। इन्हें दो घंटों में इनकी गिनती करने को कहा गया था। इसका बड़ा कारण यह है कि गिद्धों की प्रकृति यह है कि उन्हें सुबह धूप खिलाने के बाद गर्मी मिलती है तो उनमें ऊर्जा आती है।

## ठिकानों पर मिलने का कारण

अगर तापमान अच्छा नहीं रहा तो वे अपने पंख आसानी से फैला नहीं पाते। सुबह का यही दो घंटे का समय होता है जब वे अपने ठिकानों पर बैठे रहते हैं। इस दौरान उनके स्थान पर उनकी गिनती की गई। हालाँकि इस बार इस बार 20 फरवरी को पहले दिन कई स्थानों पर बारिश हुई जिससे देर से गिनती हुई। इंदौर वन मंडल में ट्रेचिंग ग्राउंड, मोहाडी फाल, चोरल आदि क्षेत्र में टीमों तीनों दिन समय पर पहुंच गई थी।

